My Notes.....

राष्ट्रीय

UN के TIR कंवेंशन में भारत शामिल

क्षेत्रीय व्यापार और ट्रांजिट हब के तौर पर खुद को स्थापित करने के क्रम में **भारत इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम 'संयुक्त राष्ट्र टीआइआर (Transports Internationaux Routiers) कंवेंशन' में शामिल होने वाला 71वां देश बन गया।** टीआइआर एक वृहत जियोग्राफिकल कवरेज के साथ इंटरनेशनल कस्टम ट्रांजिट सिस्टम है।

क्या है

1. **इस कनवेंशन के तहत सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कस्टम के अंतर्गत अपने माल को बिना किसी कर के आयात और निर्यात कर सकते हैं।** टीआईआर कनवेंशन को यातायात समझौते से बढ़कर देखा जाता है जो कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में मजबूती लाता है।

2. **टीआईआर कंवेंशन के जरिए भारत अपना व्यापार दक्षिण एशिया एवं उसके बाहर बढ़ा सकता है।** भारत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अलग-अलग देशों की ट्रांसपोर्ट और कस्टम सिस्टम के अनुरूप नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था लेकिन टीआईआर को लागू करने के बाद भारत को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
3. टीआईआर माल परिवहन के लिए मानक है जिसका प्रबंधन विश्व सड़क परिवहन संगठन (आईआरयू) के हाथों में है। आईआरयू ने ही टीआईआर विकसित किया है।
4. आईआरयू के महासचिव उमबर्टो डि प्रेटो ने कहा, श्मैं देशों के टीआईआर परिवार में भारत का स्वागत करता हूं। यह दक्षिण एशिया में परिवहन, व्यापार और विकास के सिलसिले में तालमेल एवं प्रोत्साहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5. **टीआईआर भारत को म्यांमार, थाइलैंड, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ व्यापारिक समेकन में मदद करेगा।** यह उसे ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में मालढुलाई और अफगानिस्तान एवं तेल समृद्ध यूरेशिया क्षेत्र तक माल परिवहन में भी सहायता पहुंचाएगा।श
6. **यह चीन के वन बेल्ट, वन रोड प्रोजेक्ट (ओबीओआर) का सामना करने के लिए भारत के पास एक मजबूत हथियार है।** अब तक ओबीओआर प्रोजेक्ट के लिए भारत के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है लेकिन इस कनवेंशन में शामिल होने के बाद से भारत भी उभरती शक्तियों में शामिल होगा।
7. **इससे भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपॉर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी)** और चाबहार प्रोजेक्ट को नई जिंदगी मिलेगी, जिस पर भारत लंबे समय से काम कर रहा है।

ट्रेडमार्क वाली पहली भारतीय बिल्डिंग

मुंबई के प्रसिद्ध **'ताजमहल पैलेस' को ट्रेडमार्क मिला है।** इसके साथ ही **114 साल पुरानी यह बिल्डिंग ट्रेडमार्क पाने वाली देश की पहली बिल्डिंग बन गई है।** मुंबई की गगनचुंबी इमारत अब दुनिया के उन तमाम ट्रेडमार्क वाली संपत्तियों

में शामिल हो गयी जिसमें **न्यूयार्क की अंपायर स्टेट बिल्डिंग, पेरिस का इफिल टावर** और **सिडनी का ओपेरा हाउस है।** आम तौर पर लोगो, ब्रांड नेम, रंगों की तालमेल, संख्या आदि ट्रेडमार्क होते हैं लेकिन **1999 में ट्रेडमार्क अधिनियम लागू होने के बाद से बिल्डिंग के डिजाइन के पंजीकरण का प्रयास कभी नहीं किया गया है।**

क्या है

1. ताजमहल पैलेस चलाने वाले इंडियन होटल्स कंपनी के जनरल काउंसल राजेंद्र मिश्रा ने बताया, **'हमने यह बिल्डिंग की विशेषता बनाए रखने के लिए किया है।** यह प्रॉपर्टी कंपनी की फ्लैगशिप है।

2. कंपनी के रेवेन्यू में इसका 2391 करोड़ का हिस्सा है। **गेटवे ऑफ इंडिया से भी पहले वर्ष 1903 में निर्मित ताजमहल पैलेस** भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण त्रिकोणीय प्वाइंट है जो बंदरगाह की ओर रास्ता दिखाने में मदद करती है।
3. IHCL के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के फैमिली फर्म शापूरीजी पैलोनजी एंड कंपनी द्वारा निर्मित **इस बिल्डिंग को प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अस्पताल में बदल दिया गया था।**
4. 2008 में आतंकी हमले के बाद धुएं की गुबार के बीच इस बिल्डिंग की इमेज मीडिया में वायरल हो गयी थी।
5. कंपनी को इस स्ट्रक्चर को रजिस्टर्ड कराने में सात माह का समय लगा। इस ट्रेडमार्क के बाद अब इस बिल्डिंग के इमेज को बगैर **लाइसेंसिंग शुल्क के भुगतान के कॉमर्शियल कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकता है।** अभी कुछ दुकानों पर होटल के फोटो के साथ फोटो फ्रेम और कफलिंक जैसे सामान बेचे जा रहे हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में एक ट्रेडमार्क वाली एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की फोटो का इस्तेमाल एक आदमी ने बियर के लोगो के रूप में किया था जिसके बाद उस आदमी को कंपनी अदालत में खींच लाई थी।

पीएसएलवी-सी38 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

इसरो ने अपने प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण यान **पीएसएलवी से 712 किलोग्राम के कार्टोसैट-2 श्रृंखला के एक उपग्रह और 30 नैनो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया।** प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। **यह पीएसएलवी का लगातार 39वां सफल मिशन था।** पीएसएलवी द्वारा लॉन्च कुल **भारतीय उपग्रहों की संख्या अब 48 हो गई है।** आने वाले दिनों में उपग्रह अपने पैनक्रोमैटिक (ब्लैक एंड व्हाइट) और मल्टीस्पेक्ट्रल (कलर) कैमरों की मदद से कई तरह की रिमोट सेंसिंग सेवाएं देगा।

क्या है

1. पीएसएलवी के साथ गए उपग्रहों में **एक नैनो उपग्रह तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी जिले की नूरुल इस्लाम यूनिवसर्टिी द्वारा डिजाइन** और विकसित किया गया।
2. यह एनआईयूसैट फसलों के निरीक्षण और आपदा प्रबंधन के सहयोगी अनुप्रयोगों के लिए तस्वीरें उपलब्ध करवाएगा।
3. **दो भारतीय उपग्रहों के अलावा पीएसएलवी के साथ गए 29 नैनो उपग्रह 14 देशों के हैं।** ये देश हैं- ऑस्ट्रिया (1), बेल्जियम (3), चिली (1), चेक रिपब्लिक (1), फिनलैंड (1), फ्रांस (1), जर्मनी (1), इटली (3), जापान (1), लातविया (1), लिथुआनिया (1), स्लोवाकिया (1), ब्रिटेन (3) और अमेरिका (10)।
4. आज के सफल प्रक्षेपण के साथ विदेशों से **भारत के पीएसएलवी द्वारा कक्षा में स्थापित किए गए ग्राहक उपग्रहों की कुल संख्या 209 पहुंच गई है।**

5. प्रक्षेपित किये गए **712 किलोग्राम वजनी कार्टोसैट-2 सीरीज के इस उपग्रह के साथ करीब 243 किलोग्राम वजनी 30 अन्य सह उपग्रहों को भी एक साथ प्रक्षेपित किया गया।** पीएसएलवी-सी38 के साथ भेजे गए। इन सभी उपग्रहों का **कुल वजन करीब 955 किलोग्राम है।**

अंतरिक्ष से दस्तक दे रहे दुश्मन को नाकाम करने में जुटा ISRO

1. अंतरिक्ष विज्ञान में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। **इसरो ने 31 सैटेलाइट के साथ एक बार फिर इतिहास रचा।** लेकिन इसरो के सामने बड़ी चुनौती स्पेस में मौजूद मलबों से सैटेलाइट की सुरक्षा की भी है।
2. इसरो का मुख्य उद्देश्य जहां एक तरफ सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करना है, वहीं सैटेलाइट की सुरक्षा करना भी है। अतंरिक्ष में मलबों से उत्पन्न खतरों को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं।

2009 का वो डरावना पल

1. **2 मार्च 2009 को धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में रूस के स्पेस स्टेशन आइएसएस के साथ एक भीषण दुर्घटना तय थी।** दरअसल एक पुराने सेटेलाइट का टुकड़ा उससे किसी भी वक्त टकराने वाला था।
2. वो टुकड़ा तेजी से अंतरिक्ष में घूम रहा था। उसकी गति लगभग 30 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की थी। स्टेशन के अंतरिक्ष यात्री इस उड़ते हुए टुकड़े को देखते ही स्टेशन से लगे **सोयुज कैपसूल** में चले गए।
3. खतरे की स्थिति में सोयुज कैपसूल को आईएसएस से अलग किया जा सकता है। लेकिन सौभाग्य से टुकड़ा चार किलोमीटर की दूरी से आइएसएस की बगल से निकल गया।
4. आखिर ये टुकड़ा कहां से आया। जवाब है, अंतरिक्ष में फैले कूड़े से। लंबे समय से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पिछले मिशनों द्वारा छोड़े गए कूड़े पर लोगों का ध्यान दिलाने की कोशिश करते रहे हैं। उनका कहना है कि छोटे से छोटे टुकड़ों की भी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि कुछ मिलीमीटर के टुकड़े भी सेटेलाइट को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े टुकड़े तो पूरे स्पेस स्टेशन या शटलयान को बर्बाद कर सकते हैं।

अंतरिक्ष मलबे का अर्थ

1. **बेकार हो चुके सैटेलाइट रॉकेट और उनके टुकड़ों की वजह से स्पेस में मलबा इकठ्ठा होता जाता है।** इन मलबों से काम कर रहे सैटेलाइट को खतरा होता है।
2. 30 हजार किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ये मलबे कार्यशील सैटेलाइट को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा स्पेस शटल्स और स्पेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।

मलबों की तलाश

1. 5 जुलाई 2016 तक यूनाइटेड स्टेट स्ट्रैटजिक कमांड ने आर्बिट में कुल 17,852 आर्टिफिशियल वस्तुओं का पता लगाया।
2. फिलहाल 1,419 सैटेलाइट प्रयोग में लाए जा रहे हैं।
3. जुलाई 2013 में 1 सेमी से भी छोटा 170 मिलियन से अधिक मलबा अंतरिक्ष में घूम रहा था।
4. 1 से 10 सेमी आकार के मलबों की संख्या 67 हजार थी।
5. 29 हजार बड़े मलबों की जानकारी भी साल 2013 में मिली।

मलबे की कमी में इसरो का प्रयास

1. **एक ही रॉकेट के जरिए इसरो ज्यादा संख्या में सेटेलाइट प्रक्षेपण में जुटा हुआ है,** ताकि अंतरिक्ष में जमा होने वाले मलबे में कमी लाई जा सके।
2. सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए ज्यादा रॉकेट के इस्तेमाल से अंतरिक्ष में ज्यादा मात्रा में मलबा जमा हो जाता है। तिरुअनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉ. के सिवान ने कहा कि **सेटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में छोड़ने के बाद रॉकेट का चौथा स्टेज बेकार हो जाता है।**

3. चौथे स्टेज में कुछ प्रोपेलेंट होते हैं जो खतरनाक होते हैं। इनके फटने से अंतरिक्ष में मलबा जमा होने की आशंका रहती है। लेकिन इस तरह की घटना से बचने के लिए इसरो ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जिससे अपना मिशन पूरा करने के बाद यह स्टेज अपने आप नाकाम हो जाएगा।
4. अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए इसरो कई गतिविधियों में शामिल है। इसके लिए इसरो **इंटर एजेंसी स्पेरस डेबरिस कमिटी (IADC) का सदस्य है** जो अंतरिक्ष में मानव निर्मित व प्राकृतिक मलबे को कम करने के लिए प्रयासरत रहता है।
5. अहमदाबाद के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC) के डायरेक्टर तपन मिश्रा ने बताया, जब भी स्पेस एजेंसी के किसी सेटेलाइट पर अंतरिक्ष के मलबे के कारण खतरा होता है तब आइएडीसी संबंधित स्पेस एजेंसी को अलर्ट करता है। 2015 से इसरो का मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार मलबे का पता लगा रहा है।

मलबों के खात्मे के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल

1. जर्मनी की ब्राउनश्वाइग यूनिवर्सिटी के कार्स्टेन वीडेमान का कहना है कि सैटेलाइट को चलाने वाले ईंधन को भी किसी तरह खत्म करना होगा, ताकि पुराने सैटेलाइट में धमाके न हों।
2. अगर इसके बावजूद ध्वस्त उपग्रह और रॉकेट के टुकड़े अंतरिक्ष में बचे रहे, तो स्मार्ट ओलेव इन्हे हटाने में मदद करेगा।
3. स्मार्ट ओलेव यानी ऑर्बिटल लाईफ एक्स्टेंशन वेहिकल एक ऐसी मशीन है, जिसे पृथ्वी से अंतरिक्ष में इन सारे टुकड़ों को जमा करने के लिए भेजा जा सकेगा।
4. जर्मनी की अंतरिक्ष कंपनी कायजर थ्रेडे, स्पेन की सेनर और स्वीडेन की स्पेस कॉरपोरेशन ने इसे विकसित किया है। तकनीकी रूप से ओलेव एक रोबोट है जो यूरोपीय टेलिकम्यूनिकेशन के सैटेलाइट यूटेलसैट को वापस अपनी कक्षा में लाने जा रहा है, ताकि भविष्य में वह अन्य सेटेलाइट की तरह नए स्पेस मिशन के लिए परेशानी न खड़ी करे।

भारत की पहली राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी

सरकार **भारत की पहली राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) को लॉन्च करेगी,** जो कि तेल एवं गैस की खोज और उत्पादन के लिहाज से भविष्य के उपयोग के लिए **देश के विशाल तलछटी डेटा (सेडिमेंटरी डेटा) को समेकित, संरक्षित और उसका रखरखाव करेगी।** केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 28 जून को राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) को लॉन्च किया, जो कि भारत को खुले रकबा लाइसेंसिंग शासन (ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रणाली) की तरफ बढ़ने में मददगार होगा, जहां कंपनियां उन क्षेत्रों का चयन कर पाएंगी जहां वो तेल एवं गैस की तलाश करना चाहती हैं।

क्या है

1. मौजूदा समय में सरकार एक अन्वेषण लाइसेंसिंग दौर में बोली लगाने के लिए पेशकश किए जाने वाले क्षेत्रों का चयन और उनकी हदबंदी (सीमांकित) करती है।
2. **खुले रकबा लाइसेंसिंग शासन (ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रणाली) के तहत,** कंपनियां एनडीआर पर जा सकती हैं और वो वर्तमान उत्पादन क्षेत्रों और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आंकड़ों को देख सकती हैं।
3. उन क्षेत्रों में से जो किसी भी लाइसेंसधारी के अधीन नहीं हैं तब वे उसके लिए एक उपयुक्त क्षेत्र तैयार कर सकते हैं और अन्वेषण एवं उत्पादन करने में रुचि प्रकट कर सकते हैं। एक बार क्षेत्र का चयन हो जाने के बाद सरकार इसे बिडिंग प्रक्रिया में शामिल कर सकती है।

देश में संचालित आठवीं मेट्रो सेवा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **कोच्चि मेट्रो रेल का लोकार्पण कर दिया** और फिर इसकी यात्रा भी की। इस मेट्रो के शुरू हो जाने के बाद अब क्षेत्रीय संपर्क में सुधार आने और कोच्चि में ट्रैफिक की भीड़भाड़ में कमी आने की उम्मीद है। **कोच्चि मेट्रो रेल की कुल लंबाई अलुवा से तिरिपुनितुरा तक 25.612 किलोमीटर है** तथा इस लाइन पर कुल 22 स्टेशन होंगे। हालांकि पहले चरण में अलुवा से पलारिवत्तोम तक 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ही मेट्रो चलाई जाएगी।

क्या है

1. **कोच्चि मेट्रो देश में संचालित आठवीं मेट्रो सेवा है** जिस पर 5181.79 करोड़ की लागत आई है।
2. कोच्चि मेट्रो रेल की कुल लंबाई अलुवा से तिरिपुनितुरा तक 25.612 किलोमीटर है तथा इस लाइन पर कुल 22 स्टेशन होंगे। हालांकि पहले चरण में अलुवा से पलारिवत्तोम तक 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ही मेट्रो चलाई जाएगी।
3. **कोच्चि मेट्रो की कोच चेन्नई के पास एल्सटॉम कंपनी ने बनाई है** और इनमें 70% भारतीय सामानों का इस्तेमाल किया गया है।
4. मेट्रो में नौकरी के लिए 1000 महिलाओं और 23 ट्रांसजेंडर्स को चुने गए हैं।
5. **कोच्चि मेट्रो की नींव 13 सितंबर, 2012** को तत्कालीन **प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह** ने रखी थी।
6. **कोच्चि मेट्रो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी।** कोच्चि मेट्रो की कुल ऊर्जा जरूरत की करीब 35 फीसद भरपाई सौर ऊर्जा से होगी। यहां हर स्टेशन पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे और यह देश की बिजली बचाने के साथ ही अपनी रनिंग कॉस्ट में भी कमी लाएगी।
7. **भारत में पहली बार यहीं पर कम्यूनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है।** इस तकनीक से न सिर्फ ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी, बल्कि गलती की गुंजाइश भी कम होगी। इस तकनीक का मकसद दो ट्रेनों के बीच उचित दूरी बनाए रखते हुए टक्कर से बचाना है।
8. **कोच्चि मेट्रो प्रोजेक्ट केरल सरकार और भारत सरकार का एक ज्वाइंट वेंचर है,** इसके लिए भारत सरकार ने 2032.91 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
9. **कोच्चि में विश्व स्तरीय मेट्रो प्रणाली से ग्रेटर कोच्चि में क्षेत्रीय संपर्क में सुधार होने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा** और इससे भीड़भाड़, यातायात अव्यवस्था, आने-जाने में लगने वाले समय, वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी।

भारत का संचार उपग्रह लॉन्च

फ्रेंच गुयाना के कोरू से 29 जून को **एरियनस्पेस रॉकेट के जरिये** भारत के **आधुनिक संचार उपग्रह जीसैट-17 का सफलतापूर्वक** प्रक्षेपण किया गया। जीसैट-17 का भार करीब 3,477 किलोग्राम है। यह उपग्रह सामान्य सी बैड, विस्तारित सी बैंड और एस बैंड में विभिन्न संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

क्या है

1. इसरो के अनुसार, यह **मौसम संबंधी और उपग्रह आधारित तलाशी एवं बचाव कार्य से जुड़े आंकड़े भेजने वाले उपकरण भी लेकर गया है।** इनसैट उपग्रह पहले ये सेवाएं उपलब्ध कराते थे।
2. श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी एमकेख3 और पीएसएलवी सीख38 के बाद इसरो इस महीने में तीसरी बार किसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है।
3. कर्नाटक के हासन स्थित इसरो के मुख्य **नियंत्रण सुविधा (एमसीएफ) केंद्र ने प्रक्षेपण वाहन से अलग होने के तुरंत बाद जीसैट-17 का नियंत्रण और संचालन अपने हाथ में ले लिया।**
4. उपग्रह के शुरूआती संकेतों के अनुसार यह सामान्य रूप से काम कर रहा है।
5. सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जीसेट-17 संचालन प्रयोग के लिए तैयार रहेगा।

यूएन टैक्स फंड में योगदान देने वाला पहला देश भारत

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के टैक्स फंड के लिए एक लाख डॉलर (करीब 64 लाख रुपये) का योगदान दिया है। वह इस फंड में सहायता राशि देने वाला पहला देश बन गया है। यह फंड टैक्स मसलों पर विचार-विमर्श में सक्रियता से हिस्सा लेने वाले विकासशील देशों की मदद के लिए बनाया गया है।

क्या है

1. **संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों** के विभाग ने बताया कि **टैक्स मामलों पर यूएन ट्रस्ट फंड फॉर इंटरनेशनल (यूएन टैक्स फंड) को पहला वित्तीय स्वैच्छिक योगदान भारत से मिला है।**

2. इस फंड का उद्देश्य कर मसलों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए बनी विशेषज्ञों की समिति के कामकाज की मदद करना है।
3. **यह समिति 2006 में बनाई गई थी** और संयुक्त राष्ट्र ने फंड के लिए स्वैच्छिक योगदान के लिए आह्वान किया था।
4. इस अपील पर योगदान देने के लिए भारत सबसे पहले आगे आया। भारत ने उम्मीद जताई है कि कर मसलों पर विकासशील देशों की सहभागिता बढ़ाने के लिए दूसरे देश भी टैक्स फंड में इसी तरह योगदान देंगे।

भारत ने फिर जीता यूएन की संस्था का चुनाव

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था ईसीओएसओसी में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। चुनाव में भारत को **एशिया प्रशांत श्रेणी में जापान के बाद सबसे ज्यादा 183 वोट मिले।**

क्या है

1. **ईसीओएसओसी की 18 रिक्तियों को भरने** के लिए मतदान हुआ था। **भारत और पाकिस्तान दोनों का तीन साल का कार्यकाल इस साल पूरा हो रहा है।** पाकिस्तान इस बार जीतने में सफल नहीं रहा।
2. **एक दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय कानून की भारतीय विशेषज्ञ नीरू चड्ढा को समुद्री कानूनों पर फैसला देने वाले अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल (आइटीएलओएस)** के 21 सदस्यीय पैनल में बतौर जज नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल नौ साल का होगा।

ISRO ने बनाई खास चिप

इसरो ने उपग्रह आधारित चिप प्रणाली विकसित की है जो अब सड़क मार्ग से सफर करने वाले लोगों को **मानव रहित रेल फाटकों पर ट्रेनको लेकर आगाह करेगी।** इससे यह पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त कोई खास ट्रेन कहां है। प्रायोगिक रूप से **मुंबई और गुवाहाटी राजधानी ट्रेन में यह प्रणाली लगाई जाएगी।** रेलवे ट्रेनों के इंजनों में इसरो में **विकसित इंटिग्रेटेड सर्किट (आईसी) चिप लगाएगा।** इससे जब ट्रेन किसी मानव रहित फाटक के नजदीक पहुंचेगी तो **हूटर सड़क मार्ग उपयोग करने वाले लोगों को आगाह करेगा।** इस परियोजना से जुड़े रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुवाहाटी और मुंबई के लिए राजधानी के रेल मार्गों पर 20 मानव रहित रेल फाटकों पर हुटर लगाए जाएंगे। परियोजना के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से इस प्रौद्योगिकी से और भी ट्रेनों को सुसज्जित किया जाएगा।

क्या है

1. **इसके तहत फाटकों से करीब 500 मीटर पहले आईसी चिप के माध्यम से हूटर बजने लगेगा।** इससे सड़क मार्ग का उपयोग कर रहे लोग और उनके साथ ही फाटक के नजदीक ट्रेन चालक भी सचेत हो जाएगा। जैसेख़ जैसे ट्रेन रेल फाटक के नजदीक पहुंचेगी, हूटर की आवाज तेज होती जाएगी। ट्रेन के पार होते ही हूटर शांत हो जाएगा।
2. सड़क मार्ग उपयोग करने वालों को सचेत करने के साथ ही उपग्रह आधारित प्रणाली का उपयोग ट्रेन पर निगाह रखने और रियलख़टाइम के आधार पर उसके आवागमन के बारे में बताने के लिए भी होगा।
3. इस प्रणाली से मुसाफिरों और अन्य लोगों को बहुत मदद मिलेगी क्योंकि अभी ट्रेन की स्थिति और आवाजाही का पता लगाने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिलहाल यह काम हाथों से किया जाता है।
4. दरअसल, मानव रहित रेल फाटकों पर लोगों की सुरक्षा रेलवे के लिए एक बड़ी चिंता है और रेलवे इससे निबटने के लिए विभिन्न तरीके खोज रहा है।
5. **अभी देश में तकरीबन 10 हजार मानव-रहित फाटक हैं** और रेलवे से जुड़े हादसों में से तकरीबन 40 फीसद इनके ही कारण हो रहे हैं।

भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण अभियान का शुभारंभ

केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा महेश शर्मा ने **उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में** गोवर्द्धन ब्लाक में खंड स्तरीय विशाल प्रतिभा खोज कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ ही **'भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण अभियान'** का

शुभारंभ किया। यह अभियान **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** कार्यक्रम के बैनर तले शुरू किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी शुरूआत **पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म सदी वर्ष मनाने के हिस्से के रूप में की थी,** जो मथुरा से सम्बद्ध थे।

क्या है

1. इसके जरिए एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा रही है जिससे **राष्ट्र के संपूर्ण कलाकार समुदाय की आक्षांए पूरी की जा सकें** और साथ ही कलाकारों और कलारूपों के एक सांस्कृतिक कोष का निर्माण करते हुए देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की जा सके।
2. मथुरा जिले में कार्यक्रम के समापन के बाद श्री महेश शर्मा ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय अन्य राज्यों में भी ऐसे ही खंड स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। ताकि देश के सभी ब्लॉकों में प्रतिभा की खोज की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
3. वर्तमान दौर में कर्नाटक के शिमोगा जिले के **शिमोगा ब्लॉक, हरियाणा में कुरूक्षेत्र जिले के थानेसर ब्लॉक, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के चोरी-चोरा ब्लॉक और झारखंड में सराईकेला- खारश्वान जिले के सराईकेला ब्लॉक को** शामिल किया गया है।

सरकार की रैंकिंग बताएगी शहर रहने लायक या नहीं

केंद्र ने रहने के लिए उपयुक्त शहरों की रैंकिंग करने के लिए एक नया सूचकांक शुरू किया। इसके तहत **देश के 116 शहरों की जिस तरह के गुणवत्तापूर्ण जीवन की पेशकश वे करते हैं,**उस आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। पहले रहने योग्य नगर सूचकांक की शुरुआत करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इसके दायरे में **प्रदेशों की राजधानियों समेत 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर आएंगे।** अपनी तरह का यह पहला सूचकांक शहरों की यह जानने में मदद करेगा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन के मामले में वे किस पायदान पर हैं। इसमें सुधार के लिए किस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

क्या है

1. **शहरों का आकलन व्यापक 79 मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।** इसमें सड़कों की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवागमन, रोजगार के अवसर, आपात सेवा, शिकायत निवारण, प्रदूषण,खुले एवं हरित स्थानों की उपलब्धता, सांस्कृतिक और मनोरंजन के अवसर शामिल हैं।
2. नए मानकों पर शहरों की रैंकिंग अगले वार्ष जारी की जाएगी। उन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान शहरी सुधारों को लागू करने में बेहतर प्रदर्शन के लिए 16 राज्यों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 500 करोड़ रुपये वितरित किए।
3. इस मामले में आंध्रप्रदेश शीर्ष स्थान पर हा। उसके बाद ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थान रहा।

स्कूली शिक्षा को मिली यूरोपीय सहायता

यूरोपीय संघ ने भारत में स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता की अंतिम किस्त जारी कर दी है। पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ स्कूली शिक्षा के लिए दी जा रही आर्थिक मदद की अंतिम किस्त के रूप में 250 लाख यूरो यानी लगभग 180 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया। इसका इस्तेमाल **सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** जैसी योजनाओं में किया जाएगा। **यूरोपीय संघ पिछले 23 सालों से भारत में स्कूली शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देता रहा** है और कुल 520 मीलियन यूरो यानी लगभग 3700 करोड़ रुपये की सहायता दे चुका है।

क्या है

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि **यूरोपीय संघ भारत में शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 800 लाख यूरो यानी लगभग 576 करोड़ रुपये की सहायता का वायदा किया था।**
2. इनमें 550 लाख यूरो की सहायता पहले ही भारत को मिल चुकी है। बाकी बचा 250 लाख यूरो जारी करने की घोषणा पिछले भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत ने पिछले हफ्ते की।
3. दरअसल **1990 के दशक में भारत स्कूली शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की तैयारी में जुट गया था।** इसके लिए 155 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था।

4. **यूरोपीय संघ ने सबसे पहले इस कार्यक्रम को आर्थिक सहायता दिया था।** इस तरह यूरोपीय संघ भारत को स्कूली शिक्षा की स्थिति सुधारने में मदद करने वाली पहली एजेंसी बन गई थी। स्कूली शिक्षा में अभी तक वह लगभग 3,700 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दे चुका है।
5. भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत टॉमज कुजलॉस्की के अनुसार कि 1994 से स्कूली शिक्षा को मिलने वाली यूरोपीय संघ की आर्थिक सहायता का सिलसिला आगे भी जारी रहा और इसमें इजाफा ही हुआ।
6. जब वाजपेयी सरकार ने आठवीं तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए **सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया तो यूरोपीय संघ ने इसमें भी मदद शुरू कर दी और 2012 में माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया तो यूरोपीय संघ ने इसकी मदद भी शुरू कर दी थी।**

भारत में बनेगा एफ-16

लड़ाकू विमान एफ-16 अब भारत में भी बनेगा। लॉकहीड मार्टिन और टाटा की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना को सोवियत के समय की फ्लीट को बदलने के लिए सैकड़ों विमानों की जरूरत है। **पेरिस एयरशो** में करार का एलान करते हुए दोनों कंपनियों ने कहा कि भारत में उत्पादन शुरू करने के बावजूद अमेरिका में नौकरियां बनी रहेंगी। **स्वीडन की कंपनी साब** भी भारतीय वायुसेना को विमान आपूर्ति करने की दौड़ में है। कंपनी ने भारत में ग्रिपेन फाइटर बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। कंपनी ने अभी भारत में किसी साझेदार का एलान नहीं किया है।

क्या है

1. टाटा और लॉकहीड का समझौता मोदी की अमेरिका की यात्रा से ठीक पहले हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका ने करीबी रक्षा संबंध बनाए है। **भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले शीर्ष तीन देशों में अमेरिका शामिल है। अन्य देश रूस और इजरायल हैं।**
2. भारत में बनने वाले एफ-16 विमान के निर्यात होने की भी उम्मीद है। **26 देशों में 3200 एफ-16 विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है।**
3. भारत में एफ-16 का अब तक का सबसे आधुनिक मॉडल ब्लॉक 70 बनेगा।
4. टाटा ग्रुप पहले से ही सैन्य मालवाहक विमान सी-130 के लिए एयर फ्रेम कंपोनेंट बना रहा है।
5. भारत ने अभी तक जेट के ऑर्डर की औपचारिक बोलियां नहीं मंगाई है। भारत कम से कम 100 से 250 विमान खरीद सकता है।

विश्व आबादी संभावना-2017 रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का मानना है कि **भारत की आबादी 2024 में चीन से अधिक हो जाएगी।** यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व आबादी **संभावना-2017 नामक रिपोर्ट में यह दावा किया है।**

रिपोर्ट में कहा गया है कि **चीन की आबादी फिलहाल 1.41 अरब है** और **भारत की 1.34 अरब है।** विश्व आबादी में दोनों देशों की क्रमश: 19 और 18 फीसद की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि **करीब सात साल में या 2024 के आसपास भारत की आबादी चीन की आबादी को पार करने की उम्मीद है।**

क्या है

1. यह **संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक अनुमान के 25वें दौर की समीक्षा रिपोर्ट है।** 24वें दौर का अनुमान 2015 में जारी किया गया था।
2. इसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत की आबादी 2022 तक चीन को पार कर जाएगी। नए अनुमान में कहा गया है कि 2024 में भारत और चीन दोनों की आबादी करीब 1.44 अरब के आसपास होगी।
3. **इसके बाद भारत की आबादी 2030 में 1.5 अरब और 2050 में 1.66 अरब होने का अनुमान है।** चीन की आबादी 2030 तक स्थिर रहने का अनुमान है जिसके बाद इसमें धीमी गिरावट आ सकती है।

4. **भारत की आबादी में 2050 के बाद कमी आ सकती है।** सामूहिक रूप से 10 देशों की आबादी 2017 से 2050 के बीच बढ़ कर दुनिया की कुल आबादी की आधी से अधिक हो जाने की उम्मीद है।
5. इन देशों में भारत, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, इथोपिया, तंजानिया, अमेरिका, युगांडा, इंडोनेशिया और मिस्र शामिल **हैं। इन 10 देशों में नाइजीरिया की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है।**

नई शिक्षा नीति (एनइपी) पर कमिटी गठित

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति (एनइपी) पर काम के लिए 1994 से 2003 तक इसरो का नेतृत्व करने वाले **वैज्ञानिक कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता** में 26 जून को **नौ सदस्यीय पैनल नियुक्त किया।** गठन के तुरंत बाद पैनल अपना काम शुरू कर देगी। मंत्रालय ने विभिन्न विशेषज्ञता और शैक्षणिक योग्यता वाली पृष्ठभूमि के लोगों को इस पैनल में शामिल किया है। यह पैनल भारतीय शिक्षा नीति को नये सिरे से गढ़ने का काम करेगी। पिछले 30 माह में एचआरडी मंत्रालय को शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, शिक्षकों , छात्रों व अन्य लोगों के हजारों सुझाव मिले। धार्मिक सम्मेलन आयोजित हुए जिसमें राज्य सरकारों ने अपने विचार दिए।

क्या है

1. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी (इसरो) की कमान संभाल चुके **कस्तूरीरंगन के अलावा पैनल में पूर्व आईएएस अधिकारी के जे अल्फोंसे कनामथानम भी हैं।** उन्होंने बताया कि इन्होंने केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें कृषि विग्यान और प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।
2. पैनल के अन्य सदस्यों में **मुंबई की एसएनडीटी विवि की पूर्व कुलपति डॉक्टर वसुधा कामत, पूर्व आईएएस अधिकारी के जे अल्फोंसे कनामथानम, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मंजुल भार्गव, मध्य प्रदेश के महू स्थित बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विवि के कुलपति राम शंकर कुरील, कर्नाटक राज्य नवोन्मेष परिषद के पूर्व सदस्य सचिव डॉ एम के श्रीधर,** भाषा संचार के विशेषज्ञ **डॉक्टर टी वी कट्टीमनी**, गुवाहाटी विवि में फारसी के **प्रोफेसर डॉ मजहर आसिफ**और उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा निदेशक **कृष्ण मोहन त्रिपाठी** को भी इस समिति में शामिल किया गया है।
3. इस समिति का गठन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि **सदस्य शिक्षा के विविध क्षेत्रों से जुड़ी विशेषज्ञता लेकर आएंगे।** महत्वपूर्ण रूप से यह समिति देश की विविधता भी दिखाती है क्योंकि सदस्य विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से आते हैं।
4. मंत्रालय को उम्मीद है कि इस विविधता से समिति को ऐसे अहम नीतिगत दस्तावेज तैयार करते वक्त विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखने में मदद मिलेगी।
5. कुछ साल पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने **पूर्व कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में नयी शिक्षा नीति पर एक समिति बनाई थी।** सूत्रों ने कहा कि इस समिति के सुझावों का भी इस्तेमाल किया जायेगा।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की शुरूआत

भारत में बायोफार्मास्यूटिकल्स के विकास को गति देने के लिए अब तक के **पहले औद्योगिकी-शैक्षणिक मिशन** की औपचारिक रूप से नई दिल्ली में 30 जून 2017 को केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भू-विज्ञान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शुरूआत करेंगे। **भारत में नवाचार (आई-3) नाम** से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में 25 करोड़ अमेरीकी डॉलर का निवेश होगा, जिसमें 12.5 करोड़ डॉलर का विश्व बैंक कर्ज देगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि **भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल्स उद्योग** में इससे बड़ा बदलाव आएगा। इससे उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक परितंत्र का भी निर्माण होगा।

क्या है

1. **भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग में काफी सक्रिय रहा है** और जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण और जरूरतमंदों के लिए कम कीमत वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों में भारत का वैश्विक स्तर पर अहम योगदान रहा है। चाहे **वह**

रोटा वायरस के टीके हों या **हार्ट वाल्व प्रोस्थेसिस** या फिर **सस्ते इंसुलिन**, भारत इनमें और कई दूसरी दवाओं के निर्माण में अग्रणी रहा है।

2. इसके बावजूद **भारत विकसित देशों की तुलना में फार्मास्यूटिकल उद्योग में 10-15 साल पीछे है** और इसे चीन, कोरिया और अन्य देशों से चुनौती मिल रही है।
3. इसकी वजह उत्कृष्टता केन्द्रों में जुड़ाव, खोजपरक अनुसंधान और उचित कोष की कमी है। इस क्षेत्र में समेकित नवाचार सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद खोज, अनुसंधान और शुरूआती विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है।
4. **भारत में नवाचार आई-3 इन कमियों को दूर करेगी** और भारत को प्रभावी बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों के क्षेत्र में डिजाइन और विकास का केन्द्र बनायेगा। इस मिशन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद (बीआईआरएसी) लागू करेगी।

एयर इंडिया के विनिवेश को सरकार की मंजूरी

सरकार ने **समस्याग्रस्त एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एयर इंडिया का विनिवेश करने के नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति दे दी है। यह काम कैसे होगा, विनिवेश की प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी, एयर इंडिया की परिसंपत्तियों, होटलों तथा कर्ज का क्या होगा इस सब पर **वित्तमंत्री की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति विचार करेगी।**

क्या है

1. **एयर इंडिया पर इस समय कुल मिलाकर लगभग 52 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। जबकि इसका संचित घाटा भी 48 हजार करोड़ रुपये के करीब है।** इसे संकट से उबारने के लिए संप्रग सरकार ने इस 2012 में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के दस वर्षीय पुनरुद्धार पैकेज का एलान किया था। परंतु लगभग 24 हजार करोड़ रुपये मिलने के बावजूद इसकी हालत में बस इतना सुधार हुआ है कि अब यह आपरेटिंग लाभ में पहुंच गई है।
2. एटीएफ के दाम घटने के कारण वर्ष 2015-16 में इसे 105 करोड़ रुपये का आपरेटिंग लाभ हुआ। लेकिन संचित घाटे और कर्ज के कारण इसके पूर्ण पुनरुद्धार की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यही वजह है कि सरकार ने इसके विनिवेश का फैसला किया है।
3. **एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर सरकार के समक्ष दो विकल्प हैं।** पहला विकल्प नीति आयोग ने सुझाया है जिसके अनुसार **एयर इंडिया का पूर्ण विनिवेश होना चाहिए।** यह सुझाव उन विदेशी एयरलाइनों के पुनरुद्धार के अनुभव पर आधारित है, जिन्हें सरकार ने पूरी तरह निजी क्षेत्र को बेचकर पीछा छुड़ाया। इनमें **ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस** तथा **आस्ट्रियन एयरलाइंस** शामिल हैं।
4. इन मामलों में सरकार ने सरकारी एयरलाइनों के संपूर्ण कर्ज को अपने ऊपर ले लिया था। जबकि दूसरा नागरिक विमानन मंत्रालय के सुझाव पर आधारित है। इसमें **एयर इंडिया की विभिन्न सब्सिडियरियों का अलग-अलग विनिवेश करने की बात कही गई है।** इस प्रस्ताव को अपनाने पर सरकार को कम से कम एयर इंडिया के 33 हजार करोड़ रुपये के कार्यशील ऋण से छुटकारा मिल सकता है। यह ऐसा ऋण है जिसका ब्याज चुकाने के लिए ही एयर इंडिया को हर साल 4500 करोड़ रुपये निकालने पड़ते हैं।
5. सूत्रों के अनुसार **टाटा समूह, स्पाइसजेट और इंडिगो** ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।
6. एयर इंडिया की **दो एयरलाइन सब्सिडियरी (एयर इंडिया एक्सप्रेस व एलायंस एयर)** तथा **छह सहायक सब्सिडियरी (होटल कारपोरेशन आफ इंडिया, एयर इंडिया चार्टर्स, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज, एयर इंडिया अलाइड सर्विसेज, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज तथा एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज)** हैं। जबकि 140 हवाई जहाजों का बेड़ा है।

7. अचल संपत्तियों के नाम पर इसके पास **मुंबई में मुख्यालय भवन के अलावा 32 एकड़ जमीन है।** इसके अलावा नई दिल्ली, लंदन, हांगकांग, नैरोबी, जापान तथा मारीशस में भी इसकी इमारतें हैं।

लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेन्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन

किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रभावी कामकाज के लिए **उचित, सटीक और मानक भार तथा मापतौल का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है,** क्योंकि यह कम तोलने और कम मापने की बेईमानी से सुरक्षा के रूप में उपभोक्ताओं के संरक्षण में अनिवार्य भूमिका निभाता है। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। श्री राम विलास पासवान ने बताया कि **लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेन्ड कमोडिटीज) नियम, 2011** को पूर्व पैक की गई वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था। इन नियमों के तहत **पहले ही पैक की गई वस्तुओं को कुछ आवश्यक लेबल लगाने वाली जरूरतों का अनुपालन करना होता है।** नियमों को लागू करने के अनुभव के आधार और हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद विभाग ने नियमों में संशोधन किया है, **जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं का संरक्षण बढ़ाना है,** लेकिन इसके साथ ही व्यापार करने के काम को सरल बनाने की जरूरत के साथ भी संतुलन बनाना है।

इन संशोधनों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1. ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर विक्रेता द्वारा **प्रदर्शित वस्तुओं के बारे में इन नियमों के तहत घोषणाएं करने की जरूरत है।** जैसे निर्माता, पैकर और आयातक का नाम और पता, वस्तु का नाम, शुद्ध घटक, खुदरा बिक्री मूल्य, उपभोक्ता देखरेख शिकायत और आयाम आदि का लेखा-जोखा होना चाहिए।
2. नियमों में विशेष उल्लेख किया गया है कि **कोई भी व्यक्ति किसी समरूप पूर्व पैक की गई सामग्री पर विभिन्न अधिकतम खुदरा मूल्य (दोहरे एमआरपी) की घोषणा नहीं करेगा,** जब तक कि नियमों के तहत इसकी अनुमति न हो। इससे उपभोक्ताओं को व्यापक लाभ होगा, क्योंकि उन्हें सिनेमा हॉल, हवाई अड्डों और मॉल आदि जैसे सार्वजनिक स्थलों पर वस्तुओं के दोहरे खुदरा मूल्यों के संबंध में शिकायत रहती है।
3. घोषणा करने के लिए **अक्षरों और अंकों का आकार बढ़ाया गया है,** ताकि उपभोक्ता उन्हें आसानी से पढ़ सकें।
4. **शुद्ध मात्रा जांच को ई-कोडिंग की मदद से अधिक वैज्ञानिक बनाया गया है।**
5. बार कोड/क्यूआर कोडिंग को स्वेच्छा के आधार पर अनुमति दी गई है।
6. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य वस्तुओं पर घोषणाओं के संबंध में **प्रावधानों को लेबलिंग विनियमों के साथ समरूप बनाया गया है।**
7. चिकित्सकीय उपकरण जिन्हें दवाइयों के रूप में घोषित किया गया है, स्टेंट, वाल्व, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, सिरिंज, ऑपरेशन के उपकरण आदि चिकित्सकीय उपकरणों के लिए उपभोक्ता परेशानी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इन उपकरणों को उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता के आधार पर बेचा जाता था। यहां तक कि एमआरपी की सीमा को भी अनेक कंपनियां प्रदर्शित नहीं कर रही थीं। एमआरपी के अलावा प्रमुख घोषणाओं को भी प्रदर्शित करने की जरूरत है। इसलिए इन्हें इन नियमों के तहत की गई घोषणाओं के तहत लाया जाता है।
8. **संस्थागत उपभोक्ता की परिभाषा को बदल दिया गया है,** ताकि किसी संस्थान द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए वाणिज्यिक लेन-देन/वस्तुओं की खुदरा बिक्री की संभावनाओं को रोका जा सके।
9. ये नियम 1 जनवरी, 2018 से लागू होंगे।

डीजल की होम डिलीवरी देने वाला भारत का पहला शहर

देश का पहला शहर बेंगलुरु है, जहां हर **घर में डीजल की डिलीवरी के लिए डीजलवाला बिल्कुल अखबार और दूधवाले की तरह आएगा।** ऑयल मिनिस्ट्री से सुझाव मिलने के एक हफ्ते बाद केंद्र इस सिस्टम को शुरू करने पर विचार कर रही थी। **15 जून को एक वर्ष पहले शुरू हुए स्टार्टअप माईपेट्रोलपंप ने तीन डिलीवरी वाहन लांच किए** जिसमें प्रत्येक की 950 लीटर की क्षमता है। अब तक **5,000 लीटर से अधिक डीजल** की डिलीवरी हो चुकी है। **यह काम डिलीवरी चार्ज के साथ है।**

क्या है

1. **100 लीटर तक की डिलीवरी के लिए 99 रुपये** और उससे अधिक के लिए **प्रति लीटर एक रुपया अधिक है।**
2. इस स्टार्टअप को 16 स्कूलों और कुछ अपार्टमेंट समेत 20 कस्टमर मिल चुके हैं। इसके लिए ऑनलाइन, फोनकॉल या फ्री एप डाउनलोड कर ऑर्डर दिया जा सकता है।
3. इस स्टार्टअप को 32 साल के आशीष कुमार गुप्ता चलाते हैं। गुप्ता ने आईआईटी-धनबाद से पढ़ाई की है। आप चाहें तो डीजल की प्री-बुकिंग भी करा सकते हैं।

देश के चौथे और पांचवें खुले में शौच मुक्त राज्य

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तराखंड और हरियाणा ने खुद को देश का चौथा और पांचवां खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया है। ये दोनों राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जो पहले ही खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू होने के ढ़ाई महीने के भीतर ही राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता का दायरा 42 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया है।

क्या है

1. उत्तराखंड में 13 जिले, 95 ब्लॉक, 7256 ग्राम पंचायतें और 15751 गांव हैं, जबकि हरियाणा में 21 जिले, 124 ब्लॉक और 6083 ग्राम पंचायतें हैं।
2. इन सभी ने क्रमश: देहरादून और चंडीगढ़ में खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया।
3. प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के आह्वान के परिणामस्वरूप यह विशेष उपलब्धि हासिल हुई। उन्होंने उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए ग्राम प्रधानों की भूमिका की सराहना की।
4. खुले में शौच मुक्त घोषित राज्य को बधाई देते हुए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि देशभर में खुले में शौच मुक्त की दिशा में जबरर्दस्त प्रगति के बाद स्वच्छ भारत ग्रामीण के लिए अगला कदम इस स्थिति को लम्बे समय तक बनाए रखने के साथ ही ग्रामीण भारत में ठोस और कचरा प्रबंधन की नियमित व्यवस्था करना होगी।
5. पांच राज्यों के खुले में शौच मुक्त होने के साथ ही देशभर में दो लाख से ज्यादा गांवों और 147 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।

संसद में पहली बार किसी फिल्म का ट्रेलर होगा रिलीज

आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म का ट्रेलर संसद भवन में रिलीज किया जाएगा। निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की फिल्म श्रागदेशश को संसद में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु का इस पर कहना था कि फिल्म को संसद भवन में रिलीज करने का मतलब स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के सम्मान के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा पहली बरा हो रहा है कि संसद भवन ने किसी फिल्म के ट्रेलर को संसद में लॉन्च करने की अनुमती दी है। जो हमारे फिल्म के लिए सम्मान की बात है।

क्या है

1. रागदेश फिल्म की कहानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन तीन अफसरों की कहानी है जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था और इस केस की ट्रायल लाल किले में हुई थी। इस वजह से इस ट्रायल को रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है।
2. इस केस में नामित अफसर थे कर्नल प्रेम सहगल, मेजर जनरल शाह नवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। उस दौर के नामी वकील सर तेज बहादुर सप्रू और अन्य ने इस केस में नॉमिनेटेड अफसरों का केस लड़ा था।
3. फिल्म में कुणाल कपूर सहित अमित साध और मोहित मारवाह मुख्य किरदार में नजर आएंगे। आपको बता दें पिछले हफ्ते ही फिल्म का टीजर पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
4. आपको बता दें तिग्मांशु की फिल्म श्पान सिंह तोमरश को साल 2013 में नेशनल अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिल चुका है।

स्मार्ट सिटी की एक और लिस्ट जारी

सरकार ने स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए **30 शहरों की एक और लिस्ट जारी** कर दी। इस तरह **अब तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल 90 शहरों का चयन कर लिया गया है। सूची में केरल की राजधानी तिरुवंतपुरम शीर्ष पर** है। जबकि **छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर दूसरे स्थान पर है।** वहीं जहां जम्मू एंड कश्मीर की दोनों राजधानी जम्मू और श्रीनगर को सूची में जगह मिल गया, मगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली को स्थान नहीं मिल सका।

क्या है

1. यहां तक कि **मेरठ भी सूची में जगह बनाने में नाकाम रहा।** जबकि जब उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहरों की लिस्ट भेजी थी, तब रायबरेली और मेरठ के बीच चयन को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। इन दोनों शहरों को छोड़िए, सूची में गाजियाबाद का भी नाम नहीं शामिल है।
2. इस बार **उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सूची में जगह बनाने में सफल रही है।** मुंबई ने इस प्रतिस्पर्द्धा में हिस्सा नहीं लिया।
3. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहरों के नाम की घोषणा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू द्वारा की गई। वैसे केंद्र द्वारा 40 शहरों के नाम की घोषणा की संभावना थी, मगर बंगाल और मुंबई द्वारा हिस्सा नहीं लिए जाने के कारण यह संख्या कम हो गई। नायडू ने बताया कि इस प्रतिस्पर्द्धा में 45 शहरों ने हिस्सा लिया, मगर इनमें से सिर्फ 30 का चयन किया गया।
4. गौरतलब है कि **स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इन 30 शहरों पर 57, 393 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है।** वहीं इनको मिलाकर अब ऐसे शहरों की कुल संख्या 90 से अधिक हो गई है और खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए आएगी।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बचत

बीते तीन सालों के दौरान **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होने वाली बचत के आंकड़े ने 31 दिसंबर 2016 को 50,000 करोड़ रुपए के स्तर को छू लिया।** यह जानकारी सरकार के ताजा आंकडों के जरिए सामने आई है। यह राशि इस वित्त वर्ष में डीबीटी के अंतर्गत भुगतान की गई सब्सिडी के बराबर है। यानी यह एक साल का सब्सिडी बचत के बराबर है।

क्या है

1. इस बचत के आंकड़े के इस वित्त वर्ष के दौरान और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के मुताबिक सरकार 31 मार्च 2018 तक 64 मंत्रालयों की कुल **533 केंद्रीय भुगतान योजनाओं को डीबीटी मैकेनिज्म के तहत ले आएगी।**
2. **मौजूदा समय में 17 मंत्रालयों की 84 योजनाओं को डीबीटी के अंतर्गत कवर किया गया है,** 31 मार्च 2015 को यह आंकड़ा 34 योजनाओं का था।
3. गौरतलब है कि मौजूदा समय में करीब 33 करोड़ लोग **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी)** के अंतर्गत अपने बैंक खातों में सीधे सब्सिडी प्राप्त करते हैं।

ओसीआइ कार्ड का आवेदन

केंद्र सरकार ने **भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआइओ) कार्ड** को भारत का **प्रवासी नागरिक (ओसीआइ)** कार्ड में बदलने के लिए आवेदन करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह आवेदन 30 जून 2017 सौंपा जाना था।

क्या है

1. गृह मंत्रालय ने **ओसीआइ कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन सौंपने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया।** पीआइओ कार्ड धारक यह आवेदन 31 दिसंबर 2017 तक सौंप सकते हैं।

2. पीआइओ कार्ड को ओसीआइ कार्ड में बदलने के लिए आवेदन सौंपने की तारीख मई 2016 से चौथी बार बढ़ाई गई है।
3. **पीआइओ कार्ड 2002 में लागू किया गया था।** विदेशी नागरिकों को लाभ देने के लिए यह कदम उठाया गया था। ऐसे विदेशी नागरिक तीसरी पीढ़ी के भारतीय मूल से संबंध स्थापित कर सकते थे।
4. **पीआइओ कार्ड 15 वर्षों तक भारत में यात्रा, काम और निवास के लिए वैध था।**

50 साल का हुआ ATM

एटीएम नाम से चर्चित ऑटोमेटेड टेलर मशीन का आज 50वां जन्मदिन है। लंदन में शुरू हुए इसके सफर की छाप से अब दुनिया का शायद की कोई कोना अछूता **हो। 27 जून 1967 को उत्तरी लंदन के इनफिल्ड कस्बे में पहला एटीएम शुरू हुआ था।** इसे **बार्कलेज बैंक ने अपनी शाखा में लगाया था।** इस मशीन के विकास का श्रेय **जॉन शेफर्ड-बैरोन और उनकी इंजीनियरिंग टीम को दिया जाता है।** एक ब्रिटिश प्रिंटिंग कंपनी डे ला रू के लिए काम करते हुए शेफर्ड और उनकी टीम ने डे ला रू ऑटोमेटेड कैश सिस्टम मशीन तैयार की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि चॉकलेट वेंडिंग मशीन से उन्हें इस मशीन को बनाने की प्रेरणा मिली थी। **बैरोन का जन्म 23 जून 1925 को शिलॉन्ग (मेघालय) में हुआ थे।** उनकी **मृत्यु 2010 में स्कॉटलैंड में हुई।**

क्या है

1. **देश में पहला एटीएम 1987 में शुरू हुआ था। इसे एचएसबीसी (हॉन्गकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)** ने मुंबई की अपनी शाखा में स्थापित किया था।
2. **40.5 एटीएम** की उपलब्धता है विश्व में व्यस्कों की प्रति एक लाख जनसंख्या पर
3. **278.7 एटीएम उपलब्ध हैं दक्षिण कोरिया** में व्यस्कों की हर एक लाख आबादी पर
4. 19.7 एटीएम ही उपलब्ध हैं भारत में हर एक लाख व्यस्क लोगों के लिए
5. **15,397 फीट की ऊंचाई पर है विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एटीएम। इसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुंजरेब दर्रा (कराकोरम पर्वत पर) पर स्थापित किया है।**
6. **14,300 फीट की ऊंचाई पर नाथु ला(सिक्किम) के कुपुप में है** देश का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कार्यरत एटीएम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका संचालक है।
7. **एटीएम की सुविधा वाला देश का पहला सबसे बड़ा विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य है। एसबीआई का यह एटीएम सेटेलाइट से संचालित होता है।**

अन्तरराष्ट्रीय

क्यूबा समझौता रद्द

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने **क्यूबा पर नए यात्रा और व्यापार प्रतिबंध लगा दिए हैं।** साथ ही, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा किए गए **क्यूबा समझौते को 'भयावह और भ्रमित' करने वाला बताते हुए इसे रद्द करने का ऐलान किया।** ट्रंप ने एक रैली के दौरान कहा, 'ओबामा प्रशासन ने क्यूबा पर लगे यात्रा एवं व्यापार प्रतिबंधों में जो ढील दी थी, उससे क्यूबा के लोगों को कोई मदद नहीं मिलेगी'। ट्रंप ने ओबामा के क्यूबा समझौते को 'एकतरफा' कहते हुए इसे रद्द कर दिया। मालूम हो कि अपने चुनाव अभियान के समय से ही **ट्रंप क्यूबा के साथ किए गए समझौते का विरोध कर रहे थे।** उन्होंने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं, तो इस समझौते को रद्द कर देंगे।

क्या है

1. वाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अमेरिका के लोग और कंपनियां अब क्यूबा के साथ कारोबार नहीं कर सकेंगी। ट्रंप ने अपने संबोधन के बाद 6 पन्नों का एक दिशानिर्देश भी जारी किया, जिसमें क्यूबा पर नए यात्रा एवं व्यापार प्रतिबंध लगाए गए हैं।
2. इन नए नियमों के मुताबिक, **अमेरिकी नागरिक क्यूबा की यात्रा नहीं कर सकेंगे।** अब अमेरिकी नागरिक केवल शैक्षणिक दौरे पर ही क्यूबा जा सकेंगे।

3. अमेरिकी कंपनियों को भी क्यूबा के साथ व्यापार करने की भी मंजूरी नहीं है। ट्रंप ने हालांकि क्यूबा में अमेरिकी दूतावास को बंद करने का फैसला नहीं किया है। ट्रंप ने कहा, 'क्यूबा में अमेरिकी दूतावास खुला रहेगा। हमें उम्मीद है कि दोनों देश शायद अधिक मजबूत और बेहतर मार्ग बना सकेंगे।' **मालूम हो कि दिसंबर 2014 में अमेरिका और क्यूबा के संबंधों में सुधार देखने को मिला था।**
4. ओबामा ने क्यूबा के साथ संबंध सामान्य करने का ऐलान किया था। ओबामा मार्च 2016 में क्यूबा की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर भी गए थे, जो **1959 के बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की पहली क्यूबा यात्रा थी।**

भारत और पुर्तगाल में ऐतिहासिक समझौता

भारत और पुर्तगाल ने अभिलेखागार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर **पुर्तगाल की राजधानी लिसबन** में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और पुर्तगाल गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच 17 मई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अंतर्गत पहले कदम के रूप में टौरे दो तोम्बो (नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल) ने 'मोनकॉस दो रीनो'(मॉनसून कॉरस्पान्डन्स) नाम से संग्रह के **62 संस्करणों की डिजिटल प्रतियां राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपी।**

क्या है

1. **ये संस्करण मूल रूप से 1568 से 1914 तक की अवधि तक के 456 संस्करणों का हिस्सा रहे हैं।** यह गोवा स्टेट आर्काइव्स के सभी रिकॉर्ड संग्रहों में सबसे बड़ा है।
2. संग्रह में लिसबन से गोवा की सीधा लिखा-पढ़ी को शामिल किया गया है और यह एशिया में पुर्तगाली विस्तार, अरबों के साथ उनके व्यापारिक विरोधियों और यूरोपीय शक्तियों तथा दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया में पड़ोसी राजाओं के साथ उनके संबंधों के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है।
3. **1605 से 1651 की अवधि के बीच की घटनाओं से जुड़े 12,000 दस्तावेजों वाले इन 62 संस्करणों को 1777 में**, गोवा से लिसबन भेज दिया गया था जहां इन्हें 'डॉक्यूमेंटोस रेमेटीदोस दा इंडिया'(भारत से भेजे गए दस्तावेज) शीर्षक से 1880 और 1893 के बीच लिसबन में एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रकाशित किया गया। मौलिक संस्करण हमेशा लिसबन में रहे हैं।
4. **240 वर्ष बाद गोवा स्टेट आर्काइव्स के संग्रह की श्रृंखलाओं में इस खाई को तब पाटा गया** जब 17 मई, 2017 को एक समारोह में पुर्तगाल में भारत की राजदूत के.नंदिनी. सिंगला, सांस्कृतिक समझौता और सहयोग कार्यक्रम इकाई की चीफ ऑफ डिविजन सुश्री टेरेसा आर्टिलहीरो फेरेरा, पुर्तगाल के पुस्तकालय, अभिलेखागार और पुस्तक महानिदेशक, डॉ. एल्मीडा लेसर्दा ने 'मोनकॉस दो रीनो' के लापता संस्करणों की डिजिटल इमेज का एक सेट भारत के अभिलेखागार महानिदेशक श्री राघवेंद्र सिंह को सौंपा जिनके नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 15-17 मई, 2017 तक पुर्तगाल की यात्रा पर था।

भारत-अफगानिस्तान गलियारा शुरू

अफगानिस्तान और भारत के बीच पहला हवाई गलियारा (एयर कॉरिडोर) परिचालन में आ गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो विमान को दिल्ली के लिए रवाना कर इस गलियारे का उद्घाटन किया।

क्या है

1. **यह रूट पाकिस्तान को बाईपास करता है।** दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वयं विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान के विमान का स्वागत किया। राष्ट्रपति घनी ने कहा, इस रूट से अफगानी निर्यात के लिए और मौके बढ़ेंगे। राष्ट्रपति घनी के सलाहकार सदीकुल्लाह मुजाहिद ने बताया , 19 जून को भारत रवाना हुए विमान से 60 टन औषधीय पौधे भेजे गए।

2. अफगानिस्तान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसलिए उसे अपने आयात और निर्यात के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। चूंकि उसके संबंध पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान के भारत के साथ कारोबार में बाधा खड़ी करता है।
3. ऐसे में इस हवाई गलियारे से पाकिस्तान की इस मनमानी पर रोक लगेगी और दोनों देशों के कारोबार में बढ़ोतरी होगी।

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के लिए दलवीर भंडारी का फिर नामांकन

भारत ने जस्टिस दलवीर भंडारी को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपने उम्मीदवार के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया है। **69 वर्षीय भंडारी अप्रैल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** में जज के पद के लिए भारी मतों से चुने गए थे। चुनाव में भारतीय उम्मीदवार जस्टिस दलवीर भंडारी को कुल 193 देशों में से 122 देशों का समर्थन मिला था। ऐसा हो सकता है कि **भंडारी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में बने रहें**, उनका वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2018 तक चलता है। **अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का कार्यालय नीदरलैंड में हेग में स्थित है।**

क्या है

1. **भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ कल भंडारी का फिर से नामांकन किया।** नामांकन की अंतिम तारीख 3 जुलाई है।
2. आईसीजे चुनाव नवंबर में होंगे और अगर **भंडारी निर्वाचित होंगे तो यहां वह नौ साल की अवधि का लंबा समय बिताएंगे।** आईसीजे में अपने कार्यकाल के दौरान, जस्टिस भंडारी काफी सक्रिय रहे, उन्होंने ग्यारह मामलों में व्यक्तिगत राय दी है। इनमें **समुद्री विवाद, अंटार्कटिका में व्हेल, नरसंहार के अपराध, महाद्वीपीय शेल्फ के परिसीमन, परमाणु निरस्त्रीकरण, आतंकवाद के वित्तपोषण और सार्वभौमिक अधिकारों** का उल्लंघन जैसे मुद्दे शामिल थे।
3. पद्मभूषण से सम्मानित जस्टिस भंडारी लगभग चालीस वर्षों से भी ज्यादा समय तक भारतीय न्याय प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। उनकी छवि बेदाग है। वह कभी वकील के रूप में, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज तो कभी अंतरराष्ट्रीय अदालत के जज के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं।
4. गौरतलब है कि **1945 में स्थापित**, आईसीजे ने कई देशों के बीच कानूनी विवाद सुलझाया और कानूनी सवालों पर महत्वपूर्ण सलाह दी है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में **कुल 15 जज होते हैं।**

सऊदी के नए उत्तराधिकारी घोषित

सऊदी के सुल्तान सलमान ने अपने भतीजे **मुहम्मद बिन नायेफ** को हटाकर अपने बेटे **मुहम्मद बिन सलमान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है।** अपने पिता के बाद अब **प्रिंस सलमान सऊदी की गद्दी पर बैठेंगे।** प्रिंस सलमान को प्रिंस बनाने की तैयार पहले से ही दिख रही थी। उनसे पहले **क्राउन प्रिंस रहे 57 साल के नायेफ से धीरे-धीरे सभी शक्तियां छीनी जा रही थीं।** प्रिंस सलमान सऊदी अरब की गद्दी के वारिसों में दूसरे नंबर पर काबिज थे, लेकिन इसके बावजूद जब से उनके पिता किंग सलमान को गद्दी मिली तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नायेफ को दरकिनार कर उन्हें वारिस घोषित किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले प्रिंस सलमान ने अप्रैल 2015 में नायेफ को क्राउन प्रिंस बनाया था।

क्या है

1. इससे पहले सऊदी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि **गद्दी के उत्तराधिकारियों की जमात में दूसरे नंबर पर खड़ा शख्स इतना मजबूत हो गया हो।**
2. किंग सलमान भी पिछले काफी समय से नायेफ को कमजोर कर प्रिंस को मजबूत करने की कोशिश करते दिख रहे थे। उन्होंने क्राउन प्रिंस नायेफ के दरबार को विघटित कर अपने कोर्ट में शामिल कर लिया। इससे भी प्रिंस की शक्तियां काफी बढ़ गईं।
3. **प्रिंस सलमान पहले से ही सऊदी के उप प्रधानमंत्री हैं।** साथ ही, वह सऊदी के रक्षा मंत्री भी हैं। उधर नायेफ को आतंरिक मंत्री के उनके पद से भी हटा दिया गया है।

सऊदी अरब में भारतीयों पर पड़ी मार

सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों के ऊपर अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। यह संकट सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी किए गए नए फरमान से उपजा है। दरअसल, **सऊदी सरकार ने डिपेंडेंट फी के नाम पर एक नया कर लगाया है,** जो वहां काम कर रहे विदेशियों को अपने साथ रह रहे आश्रितों के लिए चुकाना होगा। **सामान्य भाषा में इसको इस तरह से समझा जा सकता है** कि यदि कोई व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के साथ वहां रह रहा है तो उसको अपने आश्रितों को वहां रखने के एवज में 100 रियाल (करीब 1700 रुपये) प्रति व्यक्ति प्रति माह चुकाना होगा।

क्या है

1. इस नए फरमान के बाद वहां रह रहे **करीब 41 लाख भारतीयों पर नया संकट खड़ा हो गया है।** इस नए फरमान से भारतीयों पर न सिर्फ आर्थिक भार पड़ रहा है, बल्कि वह अपने परिवार को वापस भेजने पर मजबूर भी हो रहे हैं। कुछ ने तो इस तरह के भार से बचने के लिए अपने परिवार को वापस भारत भी भेज दिया है। इतना ही नहीं इस कर को एडवांस्ड चुकाना होगा। हालांकि **सरकार का यह नया फरमान 1 जुलाई से लागू होना है,** लेकिन इससे होने वाले आर्थिक बोझ को जानकर कुछ भारतीयों ने यह कदम उठाया है।
2. **विदेशियों के तौर पर सऊदी अरब में सबसे अधिक भारतीय ही रहते हैं।** इन लोगों के लिए सरकार द्वारा लगाया गया नया कर परेशानी का सबब बन गया है। पिछले चार माह में कई भारतीयों के परिवार सऊदी अरब से वापस आ गए हैं।
3. इतना ही नहीं यह कर साल-दर-साल बढ़ता जाएगा और 2020 तक यह 400 रियाल प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह हो जाएगा। उस वक्त एक आश्रित पर करीब 6900 रुपये खर्च करने होंगे।
4. यदि फिलहाल वहां पर रहने वाले भारतीयों की बात कही जाए तो इक्मा (रेजिडेंस परमिट) बढ़वाने के लिए उन्हें यह कर एडवांस चुकाना होगा। यदि किसी भारतीय के साथ उसकी बीवी और दो बच्चे सऊदी अरब में रहना चाहेंगे तो भविष्य में उन्हें इसके लिए 62000 रुपये हर वर्ष चुकाने होंगे। हालांकि इस फैसले के बाद वहां पर कुछ कंपनियों ने इसकी क्षतिपूर्ति करने की भी बात कही है। लेकिन कई लोग इसको गैर-इस्लामिक मानते हैं।

भारत को मिलेंगे 22 अमेरिकी निगरानी ड्रोन

ट्रंप प्रशासन ने भारत को निगरानी करने वाले **22 अमेरिकी गार्जियन ड्रोन देने का फैसला लिया है।** आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी। उनके अनुसार **ट्रंप सरकार ने दो से तीन अरब डॉलर (128 अरब रुपये से लेकर 192 अरब रुपये) के ड्रोन सौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है।** भारत ने अमेरिका के इस कदम को द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से गेम चेंजर करार दिया है।

क्या है

1. सरकार के उच्चस्तरीय सूत्रों का कहना है, **'अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से भारत सरकार और ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स'** को ही अवगत करा दिया था।
2. द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। सूत्र कहते हैं कि भारत के साथ संबंधों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं। यह उसका पहला महत्वपूर्ण संकेत है।
3. ध्यान रहे कि **भारत निगरानी करने वाले अमेरिकी गार्जियन ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश में काफी समय से लगा हुआ था।** ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका ने ड्रोन तकनीक भारत को देने का वादा भी कर लिया था, परंतु डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इस सौदे को लेकर संशय था।
4. ओबामा के कार्यकाल में **भारत को सबसे अहम रणनीतिक साझेदार का दर्जा देने वाला प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस में पारित हुआ था।** इससे यह ड्रोन तकनीकी भारत को मिलने का रास्ता खुल गया था। गार्जियन ड्रोन मिलने से भारत के लिए अब हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में काफी आसानी हो जाएगी।

नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए 'आधार' वैध दस्तावेज नहीं

नेपाल और भूटान की यात्रा पर जाने के लिए 'आधार' पहचान का वैध दस्तावेज नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। नेपाल और भूटान की यात्रा पर जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होती, अगर उनके पास **चुनाव आयोग से जारी मतदाता पहचान पत्र या वैध भारतीय पासपोर्ट है।** हालांकि, यात्रा में सहूलियत के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गो और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उम्र और पहचान का फोटो वाला कोई दस्तावेज दिखाना होगा। इसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार का स्वास्थ्य सेवा कार्ड या राशन कार्ड शामिल हैं। लेकिन, गृह मंत्रालय ने साफ किया कि इन दोनों देशों की यात्रा के लिए आधार मान्य नहीं होगा। इस सरकारी परिपत्र का महत्व इसलिए भी है क्योंकि **एलपीजी सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए 'आधार' अनिवार्य है।**

क्या है

1. **सड़क मार्ग से भूटान में प्रवेश करने वाले भारतीयों को वैध यात्रा दस्तावेज के आधार पर रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के आव्रजन कार्यालय से 'एंट्री परमिट' हासिल करना होता है।**
2. यह कार्यालय पश्चिम बंगाल में जयगांव के सामने भारत-भूटान सीमा पर स्थित है। जबकि नेपाल की सीमा पूरी तरह खुली हुई है और देश में प्रवेश करने वाले लोगों को सिर्फ वैध पहचान पत्र दिखाना होता है।
3. मालूम हो कि **नेपाल की सीमाएं पांच भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से छूती हैं।** इस देश में करीब छह लाख भारतीय रहते हैं।
4. जबकि, **भूटान की सीमाएं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से छूती हैं।** इस देश में करीब 60 हजार भारतीय रहते हैं।
5. इनमें अधिकांश भारतीय पनबिजली घरों और निर्माण उद्योग में कार्यरत हैं। इसके अलावा आठ से दस हजार दैनिक श्रमिक प्रतिदिन भूटान आते-जाते हैं।

ब्रिटेन में 300 साल पुरानी परंपरा टूटी

कनाडा मूल की 24 वर्षीय सैनिक कैप्टन मेगन काउटो ने ब्रिटेन की 300 साल पुरानी परंपरा तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। वे बकिंघम पैलेस की सुरक्षा में तैनात **ट्रूप की कमांड करने वाली पहली महिला बन गई है।** मेगन 3 जुलाई तक यह भूमिका संभालेंगी।

क्या है

1. उन्होने वेलिंगटन बैरक से बकिंघम पैलेस तक मार्च करते हुए ट्रूप को कमांड किया और पद संभाला। मालूम हो **बकिंघम पैलेस ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निवास है।**
2. मालूम हो, **ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स में महिलाओं पर पाबंदी थी।** इसीलिए महारानी के गार्ड के रूप में भी कोई महिला सेवा नहीं दे सकती थी। यह पाबंदी जुलाई 2016 में हटा ली गई थी।
3. इसके बाद यह पहला मामला है जब मेगन की नियुक्ति की गई है। कैप्टन मेगन और उनकी यूनिट (प्रिंसेस पैट्रिशिया लाइट इन्फेंट्री) को **कनाडा के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर महारानी के गार्ड के रूप में सेवा देने के लिए अस्थायी रूप से आमंत्रित किया है।**

साइबर हमलों को लेकर चीन और कनाडा के बीच हुआ समझौता

पूरी दुनिया के लिए साइबर हमला एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इस बीच, इसको लेकर चीन और कनाडा के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत चीन अपने देश से कनाडा के प्राइवेट सेक्टर पर होने वाले साइबर हमलों को रोकेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के हवाले से **द ग्लोब एंड मेल** ने इसकी जानकारी दी है।

क्या है

1. यह समझौता **ओटावा में कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी वांग योंगकिंग और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार डेनियल जीन के बीच बातचीत के दौरान हुआ।** दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर सहमति हुई कि ना तो देश की सरकार साइबर हमले करेगी और ना ही किसी तरह से इसका समर्थन करेगी।

2. इस समझौते के तहत **चीन सिर्फ आर्थिक जासूसी पर लगाम कसेगा।** कनाडा सरकार या सेना के खिलाफ अपने देश से संचालित साइबर हमलों को रोकने के लिए वह बाध्य नहीं है।
3. फिलहाल इस मसले पर चीनी विदेश मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय से भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

चीन ने समुद्र में उतारा 'मिसाइल डिस्ट्रॉयर'

चीन लगातार अपनी नौसैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने दुनिया की सबसे ताकतवार पनडुब्बी को समुद्र में उतारा था। इससे पहले उसने स्वदेशी तकनीक से बने युद्धपोत को पानी में उतारा था। अब चीन ने इसी कड़ी में **स्वदेशी निर्मित मिसाइल डिस्ट्रॉयर को नौसेना में शामिल किया है। टाइप 055 क्लास का यह गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दस हजार टन वजनी है** और इस पोत को शंघाई में समुद्र में उतारा गया। चीनी मीडिया के मुताबिक यह पोत चीन की नौसेना के लिए काफी अहम साबित होगा।

क्या है

1. इस पोत पर **जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, क्रुज मिसाइल, एंटी शिप क्रुज मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल लगी हैं।**
2. यह युद्धपोत जमीनी लड़ाई में भी काफी सहायक साबित होगा। **वर्ष 2030 तक चीनी नौसैनिक बेड़े में करीब 415 युद्धपोत होंगे** जबकि **अमेरिका पास केवल 309 युद्धपोत होंगे।** उस वक्त चीन की नौसेना के पास 99 पनडुब्बियां, चार विमानवाहक युद्धपोत, 102 विध्वंसक युद्धपोत, 26 वाहक पोत, 73 दोहरे उपयोग के पोत और कुल 111 मिसाइलों से लैस युद्धपोत होंगे।
3. चीन अपने लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लिए पनडुब्बियों को बेचना उसके आर्थिक कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अमेरिका की एक मैगजीन ने वर्ष 2030 में विश्व की जिन सबसे ताकतवर नौसेनाओं का जिक्र किया है उसमें चीन भी शामिल है।
4. चीन के अलावा इसमें **भारत, अमरीका और ब्रिटेन भी शामिल है।** इसका आधार उस वक्त किसी देश के बाद मौजूद विमानवाहक युद्धपोत और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां होंगी।
5. **वर्ष 2030 तक भारत की नौसेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना होगी** और उसके पास तीन विमानवाहक युद्धपोत होंगे। इनमें विक्रमादित्य, विक्रांत और विशाल का नाम शामिल है।
6. इनके अलावा भारतीय नौसेना में कम से कम नौ विध्वंसक युद्धपोत भी होंगे, जिनमें से दो युद्धपोत गाइडिड मिसाइल से लैस कोलकाता वर्ग के, तीन दिल्ली वर्ग के और चार विशाखापत्तनम वर्ग के होंगे। इनका निर्माणकार्य फिलहाल चल भी रहा है।
7. इसके अलावा **भारतीय नौसेना की ताकत बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पहली अरिहन्त पनडुब्बी के आने से और भी बढ़ गई है।** वर्ष 2030 तक भारत के पास छह पनडुब्बियों का एक शक्तिशाली बेड़ा होगा।

अर्थशास्त्र

स्टार्ट अप इंडिया हब का शुभारम्भ किया

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने **नई दिल्ली में ऑनलाइन स्टार्ट अप इंडिया हब का शुभारम्भ किया,** जहां भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी भागीदार एक मंच पर आकर परस्पर खोज करेंगे, सम्पर्क में रहेंगे और एक दूसरे से राय-मशविरा करेंगे। यह **मौजूदा और संभावनाशील स्टार्ट अप के जीवनचक्र को आसान व कारगर बनाएगा।** उन्हें सही समय पर सही संसाधनों तक पहुंचने में मददगार होगा। उन्होंने इस पोर्टल का भारत में उपयोग करने के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया और सभी भागीदारों को इस मंच को अधिक से अधिक सक्षम बनाने में अपना योगदान देने को आग्रह किया। मंत्री महोदया ने एक नई पहल की घोषणा की, **जिसमें स्टार्ट अप का सार्क देशों में विचार-विमर्श के कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।**

क्या है

1. **यह पोर्टल स्टार्ट अप, निवेशक, वित्त, संरक्षक, अकादमिक, इन्क्यूबेटर्स, उत्प्रेरक, कॉरपोरेट्स, सरकारी निकाय और अन्यान्यों की मेजबानी करेगा।** यह हब सूचनाओं में विसंगति की समस्या और खास कर देश की दूसरी व तीसरी श्रेणी के नवजात पारिस्थितिकी तंत्र वाले शहरों में जानकारियों, उपकरणों व विशेषज्ञों तक पहुंच की कमी को दूर करने की कोशिश करेगा।
2. स्टार्ट अप के लिए वर्चअुल हब एक गत्यात्मक और संवादी मंच होगा, जो उनके शिक्षण एवं विकास, नेटवर्किंग, संरक्षण, वित्तपोषण आदि को सुगम बनाएगा।
3. इस पोर्टल को विकसित करने का बुनियादी सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रस्तावों को एक जगह एकत्र करना है। स्टार्ट अप इंडिया अनेक संगठनों के ऑन बोर्ड उद्यमियों और निवेशकों के साथ भागीदार रहा है। साथ ही, वह ज्ञान के मॉडयूल का सर्जक भी। विभिन्न मंचों तक पहुंच बनाने की गरज से एक प्रतिबद्ध एप्स एंड्रोयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है।
4. **भारत पूरी दुनिया में स्टार्ट अप पारिस्थितिकी तंत्र वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है,** जहां रोजाना तीन से चार स्टार्ट अप अपना काम शुरू करते हैं। यह हब एक नोडल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा और उपयोगकर्ताओं को पारिस्थितिकी तंत्र के भागीदारों से सम्पर्क करने, शिक्षण संसाधनों तक फ्री पहुंच, कानूनी उपकरणों व आदर्शों, मानव संसाधन, लेखा और नियामक मामलों और संवाद के मंच से जुड़ने में उन्हें सक्षम करेगा।
5. **इस हब में सरकार के प्रासंगिक 50 योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।** दूसरे चरण में, यह प्लेटफॉर्म राज्य सरकारों की स्कीमों का समुच्चय करेगा। स्टार्टअप उपयोगकर्ताओं के बेहतर अनुभव दिलाने के लिए, यह प्लेटफार्म चार्टबूट्स के साथ स्वत: सभी जगहों से सूचनाओं को एकत्र करने , अद्यतन सूचना और सवालों के जवाब दे कर स्मार्ट मेधा का सृजन करता रहा है।
6. **स्टार्ट अप हब के उद्घाटन के अवसर पर 'स्टार्ट अप परिदृश्य का मार्गदर्शन' नाम से एक विचार-सत्र का भी आयोजन किया गया,** जिसमें हरेक स्टार्ट अप, निवेशक, इन्क्यूबेटर, उत्प्रेरक और संरक्षक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
7. विचार सत्र के बाद औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव श्री रमेश अभिषेक ने स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू की गई अनेक पहलों पर एक प्रेजेंटेशन दिया।
8. संयुक्त सचिव राजीव अग्रवाल ने अपने समापन भाषण में स्टार्ट अप इंडिया के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सभी भागीदारों से हब में अपने नाम को दर्ज कराने का अनुरोध किया।

दिवालिया कानून का अमल होगा आसान

बैंकों **के आठ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के फंसे कर्जों (एनपीए) की समस्या** से निपटने के प्रयासों में **बाजार नियामक सेबी** भी शामिल हो गया है। **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)** ने कर्ज संकट में फंसी लिस्टेड कंपनियों के पुनर्गठन की खातिर अपने अधिग्रहण के नियमों को नरम बना दिया है। इस ढील की वजह से **निवेशक को ऐसी कंपनी को खरीदने पर ओपन ऑफर लाना अनिवार्य नहीं होगा।** यह फैसला सेबी के निदेशक बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया। इसके अलावा बोर्ड ने पी-नोट्स जारी करने पर सख्ती करने समेत कई और कदमों को भी मंजूरी दी।

क्या है

1. **कर्ज में फंसी लिस्टेड (स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध) और इनसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड** के तहत स्वीकृत समाधान योजना वाली फर्मो के पुनर्गठन के लिए नियम आसान होंगे।
2. इसका मकसद बैंकों के वसूल नहीं हो पा रहे कर्जों की समस्या से निपटने के प्रयासों में सरकार और रिजर्व बैंक की मदद करना है। नए कदमों से संकटग्रस्त सूचीबद्ध कंपनियों के पुनरोद्धार में सहूलियत होगी। इसका फायदा कंपनियों को कर्ज देने वालों और शेयरधारकों को मिलेगा।

3. फिलहाल कर्जदाताओं को **रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन (एसडीआर) स्कीम** के तहत जिन लिस्टेड कंपनियों का पुनर्गठन किया जा रहा है, उन्हें ही तरजीही शेयर जारी करने संबंधी अपेक्षाओं और ओपन ऑफर की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है।
4. सेबी के पास उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से कई बार ऐसी मांग रखी गई जिन्होंने कर्ज के एवज में ऐसी कंपनियों के शेयर ले रखे हैं। ये कर्जदाता अब इन शेयरों को नए निवेशक को बेचना चाहते हैं। ऐसे निवेशक इन शेयरों के अधिग्रहण से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खुली पेशकश करनी होती है।
5. **सेबी ने पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के नियमों को कड़ा कर दिया है।** कड़े कदम के तहत प्रत्येक पी-नोट पर 1,000 डॉलर का शुल्क लगाया जाएगा। इसे एक अप्रैल, 2017 से हर तीन साल पर जारीकर्ता एफपीआइ एकत्र और जमा करेगा।
6. **हेजिंग को छोड़कर सट्टेबाजी के मकसद से पी-नोट्स जारी करने पर पाबंदी** होगी। अलबत्ता बाजार नियामक ने इन पर पूरी तरह रोक लगाने की संभावना से इन्कार किया है।
7. नियामक के ताजा उपायों का मकसद काला धन को सफेद बनाने के लिए नियमों का दुरुपयोग रोकना है। सेबी चेयरमैन ने कहा कि नियामक पी-नोट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ नए निवेशक इसी रास्ते से भारतीय बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं।

क्या हैं पी-नोट्स

1. **विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआइआइ या एफपीआइ (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) भारतीय शेयरों व प्रतिभूतियों पर आधारित विदेश में निवेश पत्र (इंस्ट्रूमेंट) जारी करते हैं।**
2. इन निवेश पत्रों को **पार्टिसपेटरी नोट** यानी पी-नोट कहा जाता है।

कालाधान पर स्विट्जरलैंड सूचनाओं को साझा करेगा

स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वचालित व्यवस्था का 16 जून को अनुमोदन कर दिया। इसके लिए **इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों का अनुपालन करना होगा।** कर संबंधी सूचनाओं के **स्वतः आदान-प्रदान (एईओआई) पर वैश्विक संधि के अनुमोदन के प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद (मंत्रिमंडल) की मुहर लग गई है।** स्विट्जरलैंड सरकार इस व्यवस्था को **वर्ष 2018 से संबंधित सूचनाओं के साथ शुरू करने का निर्णय लिया है।** इसके लिए आंकड़ों के आदन प्रदान की शुरुआत 2019 में होगी।

क्या है

1. स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था शुरू करने की तिथि की सूचना भारत को जल्द ही देगी। **परिषद द्वारा इस संबंध में स्वीकृत प्रस्ताव के मसौदे के अनुसार** इसके लिए वहां अब कोई जनमत संग्रह नहीं कराया जाना है। इससे इसके लागू किए जाने में विलम्ब की आशंका नहीं है।
2. **कालेधन का मुद्दा भारत में सार्वजनिक चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ है** तथा लंबे समय से एक धारणा है कि बहुत से भारतीयों ने अपनी काली कमाई स्विट्जरलैंड के गुप्त बैंक-खातों में छुपा रखी है।
3. भारत विदेशी सरकारों, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ अपने देश के नागरिकों के बैंकिंग सौदों के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर जोरदार प्रयास करता आ रहा है।
4. स्विट्जरलैंड ने आज जिस बहुपक्षीय एईओआई व्यवस्था का अनुमोदन किया है वह ऐसे प्रयासों का ही नतीजा है ताकि **विदेश के रास्ते कालेधन को खपाने और मनी लांडरिंग पर कारगर अंकुश लगाया जा सके।**
5. सूचनाओं का आदान प्रदान इसके लिए एक **सक्षम बहुपक्षीय प्राधिकरण हेतु समझौते (एमसीएए) के आधार पर किया जाएगा।** सूचनाओं के आदान प्रदान के नियम पेरिस स्थित संगठन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने तैयार किए हैं।

इंटरनेशल आर्बिट्रेशन में अपनी चुनौती को RIL ने लिया वापस

अरबपति मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनकी ब्रिटिश सहयोगी बीपी पीएलसी ने उस कानूनी चुनौती को वापस ले लिया है, जिसे **गैस कीमत संशोधन में देरी के चलते सरकार के खिलाफ तीन साल पहले दाखिल किया गया था।** इस मुकदमे को वापस लिए जाने से अब इन दोनों कंपनियों को **नए गहरे क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस के विपणन और उसकी कीमत तय करने की आजादी होगी।**

क्या है

1. **इसमें वह गैस है, जिसका उत्पादन 2022 तक 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू किया जाना है।** सूत्र ने बताया कि आरआईएल के मुकेश अंबानी और बीपी के सीईओ बॉब डडली की 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद ही इन दोनों कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
2. अंबानी व डडली ने एक संवाददाता सम्मेलन में अपने केजी डी6 ब्लॉक में निवेश चक्र आठ साल के बाद फिर शुरू करने की घोषणा की और कहा कि कंपनियां गहरे समुद्र में खोजों के तीन सैट के विकास में 40000 करोड़ रुपए निवेश करेंगी।
3. गौरतलब है कि डडली ने जनवरी 2015 में मोदी के साथ अपनी पिछली मुलाकात में गैस कीमत में स्वतंत्रता की सुविधा मुश्किल क्षेत्रों में अविकसित गैस क्षेत्रों को भी देने का पक्ष लिया था।
4. सरकार ने इस पर सहमति जताई और शर्त रखी की कंपनियां सरकार की गैस कीमत नीति को चुनौती देने वाले किसी भी आर्बिट्रेशन चुनौती या कानूनी चुनौती को वापस लेंगी।

जीएसटी के लिए टीडीएस और टीसीएस फिलहाल टाला

वस्तु एंव सेवा कर कानून जीएसटी के देशभर में लागू होने को अब सिर्फ कुछ दिन का ही समय शेष बचा है। ऐसे में **सरकार ने टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है।** साथ ही ई-कॉमर्स के जरिए बिक्री करने वाली छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन से छूट भी दे दी गई है। फिलहाल **ई-कॉमर्स कंपनियों को वस्तु और सेवा कर के तहत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय 1 फीसद टीसीएस (टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स) इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी।** आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर देशभर में 1 जुलाई से लागू किया जाना है।

क्या है

1. **केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कानून के अंतर्गत अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्त के लिये** भुगतान पर **एक फीसद टीडीएस संग्रह की आवश्यकता है।** इस प्रावधान को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
2. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि व्यापार एवं उद्योगों से मिली प्रतिक्रियाओं के मुताबिक **सरकार ने सीजीएसटी (स्टेट जीएसटी कानून, 2017) के तहत टीडीएस (धारा 51) तथा टीसीएस (धारा 52)** से जुड़े प्रावधान को आगे टालने का निर्णय किया है। इस कदम का उद्देश्य जीएसटी का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
3. गौरतलब है कि जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ने टीडीएस, टीसीएस कटौती करने वालों तथा ई-वाणिज्य परिचारकों का पंजीकरण 25 जून से फिर से शुरू कर दिया है।

40 साल के सफर के बाद मुकाम पर GST

71 साल पहले 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। **अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार की दिशा में पहली बार 1978 में गंभीरता से मंथन हुआ।** करीब चालीस साल के बाद देश के राजनेताओं में ये सहमति बनी कि अब देश को एक आर्थिक इकाई में बदलने की जरूरत है। लेकिन अप्रत्यक्ष करों के सफरनामे पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि **30 जून की मध्यरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है।** आज की रात ऐतिहासिक है। संसद के केंद्रीय कक्ष में घंटा बजाने के साथ ही पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू हो गया है। देश के राज्यों की सीमाएं भले ही एक-दूसरे को अलग करती हों। लेकिन **आर्थिक रूप से पूरा देश एक इकाई में बदल जाएगा।** संसद के विशेष सत्र में जिस वक्त जीएसटी लागू होगा वो उस तस्वीर को याद दिला रहा होगा, जब देश के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू ने देश के साथ एक वादा किया था। पीएम

नरेंद्र मोदी उस ऐतिहासिक क्षण पर देश को संबोधित किये है। लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि जीएसटी को मंजिल पर पहुंचने के लिए जमीन पर सफर तय करने में कितना समय लगा।

जीएसटी का सफरनामा

1. **1978 - एल के झा की अगुवाई में एक समिति ने अप्रत्यक्ष कर को मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स (MODVAT) में बदलने का सुझाव दिया था।** एल के झा लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव होने के साथ-साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे।
2. **1986 - राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे वी पी सिंह ने बजट में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स (MODVAT) को शामिल किया।** इस पूरी कवायद का मकसद था कि उत्पादनकर्ता को कंपोनेंट और कच्चे माल पर अदा किए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी की जल्द से जल्द भरपाई की जा सके। इसके साथ ग्राहकों को महंगाई से राहत दिलाई जा सके।

जीएसटी आने के बाद कितने तरह के कर खत्म हो जाएंगे

1. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी
2. एक्साइज ड्यूटी (medicinal and toilet preparations)
3. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज (विशेष महत्व की वस्तुओं पर)
4. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर)
5. कस्टम पर एडिशनल ड्यूटी (इसे सीवीडी के नाम से जानते हैं)
6. स्पेशल एडिशन ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी)
7. सर्विस टैक्स
8. वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित सेस और सरचार्ज
9. स्टेट वैट
10. सेंट्रल सेल्स टैक्स
11. पर्चेज टैक्स
12. लग्जरी टैक्स
13. एंट्री टैक्स (ऑल फॉर्म)
14. एंटरटेनमेंट टैक्स (स्थानीय निकायों की ओर से नहीं लगाए गए)
15. विज्ञापन पर टैक्स
16. लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर
17. स्टेट सेस और सरचार्ज

3. **1991-92- पी वी नरसिंहाराव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने राजा चेलैय्या की अध्यक्षता में टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाया।** आयोग ने माडवैट (MODVAT) की जगह वैट और सर्विस टैक्स लागू करने का सुझाव दिया। सेवाओं को 1994 में पहली बार टैक्स के दायरे में लाया गया।
4. **1997- एच डी देवेगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने अपना ड्रीम बजट पेश किया।** उन्होंने पीक कस्टम ड्यूटी को 50 फीसद से 40 फीसद करने का फैसला किया। इसके अलावा टैक्स संरचना में और सुधार करने पर जोर दिया।
5. 1999- अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने टैक्स सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया। केंद्र और राज्यों के बीच सेल्स टैक्स को लेकर जो विवाद पहले से चल रहा था उसे खत्म करने की कोशिश की गई। टैक्स की जटिल प्रणाली को सरल बनाने की पहल हुई। संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अगुवाई में एक एंपावर्ड कमेटी का गठन किया और पूरे देश में वैट लागू करने की योजना पर काम शुरू हुआ।
6. **2001-02- एक अप्रैल 2002 को वैट को लागू करने का फैसला किया गया।** लेकिन भाजपा शासित राज्यों के साथ-साथ दूसरे राज्यों के विरोध की वजह से इसे एक साल के लिए टाल दिया गया।

7. **2003- अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।** इस समिति ने फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) एक्ट का सुझाव दिया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पहला स्वरूप तय हुआ। कमेटी ने राज्यों के लिए 7 फीसद और केंद्र के लिए 5 फीसद टैक्स तय करने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही वैट को 1 अप्रैल 2005 तक के लिए टाल दिया गया।
8. **2005- एक अप्रैल 2005 को स्टेट वैट लागू किया गया।**
9. **2007- वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट स्पीच में अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का ऐलान किया।** इसके लिए एक एंपावर्ड कमेटी का गठन किया गया। आम सहमति बनाने के लिए असीम दासगुप्ता और सुशील कुमार मोदी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर आम सहमति बनाने में जुट गए ।
10. 2009- वित्त मंत्री के सलाहकार पार्थसारथी शोम ने जीएसटी पर पहला पेपर पेश किया।
11. **2009-10- जीएसटी को शामिल करने के लिए 13वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दायरे को बढ़ाया गया।** आयोग ने राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई का सुझाव दिया।
12. 2011- वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी फ्रेमवर्क के लिए 115वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्थाई समिति को ये बिल भेजा गया। स्थाई समिति ने 2013 में रिपोर्ट पेश की। लेकिन भाजपा शासित राज्यों और तमिलनाडु ने बिल का जबरदस्त विरोध किया।
13. 2013-14- यूपीए सरकार जीएसटी बिल को संसद से पारित कराने में नाकाम रही। लेकिन इंफोसिस के पूर्व सीइओ नंदन नीलेकणि की अगुवाई वाली कमेटी ने द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन नेटवर्क को प्रमोट करने की संस्तुति की।
14. 2014-15- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिसंबर 2014 में लोकसभा में जीएसटी से संबंधित संशोधन बिल पेश किया जिसे 2015 में लोकसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा से बिल को पारित होने के बाद राज्य सभा की सलेक्ट कमेटी को भेजा गया।
15. 2016- राज्यसभा ने जीएसटी बिल को पारित कर दिया, इसके साथ ही अलग-अलग तरह के सामानों की दरों को निर्धारित करने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। सरकार की मंशा थी कि एक अप्रैल 2017 से जीएसटी को लागू किया जाए, लेकिन बाद में उस तिथि में बदलाव किया गया।
16. 2017- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अलग-अलग दलों के कद्दावर नेताओं और राज्यों से लगातार बातचीत की और जीएसटी को एक जुलाई 2017 से लागू करने का ऐलान किया।

विज्ञान एवं तकनीकी

मलेरिया का सटीक पता लगाएगी नई जांच

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खून की जांच विकसित की है जो मलेरिया की सटीक पहचान कर सकती है। यह मौजूदा विधियों की तुलना में बहुत तेजी से जांच करने में सक्षम है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस संक्रामक बीमारी से सबसे बड़ी समस्या इसकी जल्दी और भरोसेमंद पहचान करने में आती है।

क्या है

1. फिलहाल खून में **रोगाणुओं का माइक्रोस्कोपिक से मुख्य रूप से पता लगाया जाता है।** इन विधियों में ज्यादा समय लगने के साथ ही नतीजे भी पूरी तरह सटीक नहीं आते हैं।
2. इसे ध्यान में रखते हुए जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने **नई जांच** विकसित की है। इसमें **30 तरह के ब्लड वेल्यू का इस्तेमाल किया गया।**
3. इस नई विधि से मलेरिया की 97 फीसद तक सटीक जांच की जा सकती है। **विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार, साल 2015 के दौरान दुनिया भर में मलेरिया से 4.3 लाख लोगों की जान गई थी।**

सूरज का भी था जुड़वा तारा

सूर्य को लेकर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। **अध्ययन के मुताबिक, 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आते समय सूर्य अकेला नहीं था।** उस समय इसके साथ एक और तारा भी बना था। वैज्ञानिकों का कहना है कि **हर तारा अपने जुड़वा तारे के साथ पैदा होता है।** वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के **पड़ोसी तारे अल्फा सेंचुरी** समेत बहुत से तारों के साथी की पहचान की है।

क्या है

1. **खगोलशास्त्रियों ने सूर्य के जुड़वा तारे को लेकर भी खोज की** और इसे काल्पनिक नाम **नेमेसिस (सजा की देवी)** दिया।
2. माना जाता है कि इसी की वजह से एक क्षुद्रग्रह धरती से टकराया था और तभी डायनासोर का अंत हो गया था। मगर अभी तक सूरज के इस जुड़वा तारे को खोजा नहीं जा सका है।
3. अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ता इस संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में मॉडल भी तैयार किया है।
4. शोधकर्ता **स्टीवन स्टेलर** ने कहा, 'हमें पूरा विश्वास है कि बहुत समय पहले निश्चित तौर पर नेमेसिस अस्तित्व में था। हमने इससे जुड़े मॉडल तैयार किए हैं।'
5. सूर्य और इसके जुड़वा तारे के बीच की दूरी सूर्य से नेपच्यून की दूरी की 17 गुना थी। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। समय के साथ यह तारा आकाशगंगा में विलीन हो गया।

दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर

चीन के सुपर कंप्यूटर ने एक बार फिर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होने का खिताब हासिल किया है। **सुपर कंप्यूटर की टॉप 500** की छमाही सूची में यह बात सामने आई है। **सूची में चीन के सनवे ताइहूलाइट को पहला और तियानहे-2 को दूसरा स्थान मिला है।** अमेरिका और जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाने वाली इस सूची में **सनवे ताइहूलाइट ने लगातार तीसरी बार पहला स्थान हासिल किया है।** इससे पहले तीन साल यानी लगातार छह बार तियानहे-2 इस स्थान पर काबिज था। **इस बार सूची में तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड के पिज डेंट को मिला है।** पहले स्थान पर रहे सनवे ताइहूलाइट की बड़ी खूबी यह है कि इसमें पूरी तरह चीन में तैयार प्रोसेसर लगा है। इसकी गति **93 पेटाफ्लोप्स (93 लाख अरब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड) पाई गई।**

क्या है

1. चीन के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर के उपनिदेशक हाओहुआन फू ने कहा, **यह सुपर कंप्यूटर बनाने की दिशा में चीन की क्षमता दिखाता है।**
2. चीन एक साथ सुपर कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का निर्माण कर रहा है। देश में तैयार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से बने सुपर कंप्यूटर कई क्षेत्रों में विकास को गति देंगे।श दूसरे स्थान पर रहे तियानहे-2 की गति 33.9 पेटाफ्लोप्स पाई गई।
3. **तीसरे स्थान पर रहे स्विट्जरलैंड के सुपर कंप्यूटर की गति 19.6 पेटाफ्लोप्स रही।** 17.6 पेटाफ्लोप्स की गति के साथ अमेरिका के ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी में स्थापित सुपर कंप्यूटर टाइटन को सूची में चौथा स्थान मिला।
4. **24 साल में पहली बार अमेरिका टॉप 3 से बाहर हुआ है।** हालांकि टॉप 10 में अमेरिका के पांच सुपर कंप्यूटर शामिल हैं।

तारों के बीच रिक्त स्थान का पता लगाएगा नासा

तारों के बीच मौजूद रिक्त स्थान के बारे में पता लगाने के लिए नासा ने CHESS (CHESS) मिशन' की योजना बनायी है। यह मिशन 27 जून से शुरू होगी। नासा के इस मिशन से शोधकर्ताओं को तारों की संरचना और निर्माण की शुरुआती चरणों को समझने में मदद मिलेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि CHESS(Colorado High & resolution Echelle Stellar Spectrograph) एक रॉकेट पेलोड है जो ब्लैक ब्रांट IX रॉकेट पर उड़ान भरेगा। पिछले तीन सालों में CHESS पेलोड के लिए यह तीसरी उड़ान होगी जो मिशन का सबसे अधिक विस्तार वाला सर्वे होगा।

क्या है

1. **अंतरिक्ष की गहराई में तारों के बीच का स्थान खाली नहीं है।** इनके बीच **उदासीन अणुओं और परमाणुओं का झुंड है** जिसके साथ प्लाज्मा पार्टिकल भी हैं जो लाखों साल में नए तारे या ग्रह का रूप लेते हैं।
2. चेस रॉकेट मिशन का फोकस तारों के बीच मौजूद रिक्त स्थान होंगे जिससे तारों की संरचना के शुरुआती प्रक्रिया का पता चल सकेगा। उन **रिक्त स्थानों से फिल्टर होने वाली रोशनी को** CHESS **के जरिए मापा जाएगा** जिससे वहां मौजूद अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन किया जा सकेगा और तारों के जीवन चक्र को समझने के लिए जानकारियां मुहैया होंगी।
3. CHESS के आंकड़ों द्वारा यह पता चलेगा कि अंतरिक्ष में कौन से अणु व परमाणु मौजूद हैं, उनके तापमान क्या हैं और वे कितनी तेजी से चक्कर काट रहे हैं।
4. वैज्ञानिकों को इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि किस तरह तारों के बीच 'क्लाउड' का निर्माण होता है जिससे उन्हें पता चलेगा कि तारों की संरचना प्रक्रिया में इनकी भूमिका क्या होती है।
5. CHESS कुल 16 मिनट के लिए ही उड़ान भरेगा। मात्र साढ़े 6 मिनट की उस उड़ान में सतह से 90 और 200 मील के फासले के बीच सर्वेक्षण किया जाएगा।

दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा **वालोप्स अंतरिक्ष केंद्र से एसआर-4 रॉकेट के जरिए कलाम सैट उपग्रह** का प्रक्षेपण करेगा, जिसकी मिशन अवधि 240 मिनट की होगी। यह उपग्रह **दुनिया का सबसे हल्का और छोटा उपग्रह है।** भारत के मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा गया है।

क्या है

1. इस उपग्रह का काम **3डी प्रिंटेड कार्बन फाइबर के कार्य का प्रदर्शन करना है।** कलाम सैट को कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके बनाया गया है।
2. इसमें तापमान और रेडिएशन स्तर को मापन के लिए सेंसर लगे हुए हैं।
3. **इस उपग्रह का वजन 64 ग्राम है,** इसलिए यह विश्व का सबसे हल्का एवं सबसे छोटा उपग्रह है।
4. इस उपग्रह को तमिलनाडु के करूर जिले में पल्लापट्टी के रिफाथ शारूक ने बनाया है। नासा और आई डूडल लर्निंग ने अंतरिक्ष से संबंधित एक प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें शारूक के उपग्रह का चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में 57 देशों की टीमों ने उपग्रहों की 86 हजार डिजाइनें दिखायी थीं।

मंगल पर मिले पुरानी झील के निशान

नासा के मंगलयान अपॉर्च्यूनिटी ने लाल ग्रह पर झील के निशान देखे हैं। यान ने यहां के **एक क्रेटर में कुछ चट्टानें देखी हैं,** जो संभवत: बाढ़ या तूफान से वहां पहुंचीं थीं। इन चट्टानों के आधार पर यहां झील के प्रमाण मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद यान को वहां नीचे उतारने की योजना बनाई है।

क्या है

1. **अपॉर्च्यूनिटी यान 2011 से यहां के इंडीवर क्रेटर के पश्चिमी छोर का अध्ययन कर रहा है।** यह क्रेटर करीब 22 किलोमीटर तक फैला है।
2. सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के रे एरविडसन ने कहा, पहले यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि खाड़ी के ठीक ऊपर क्या है। उसके बाद यान अंदरूनी हिस्सों का अध्ययन करेगा।
3. हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां जो चट्टानें मिली हैं, वे यहीं की हैं या कहीं से बहकर आई हैं।
4. वैज्ञानिकों ने बताया कि चट्टानों की संरचना और उनके बारे में विस्तृत जानकारी से मंगल पर पानी होने के प्रमाण मिल सकते हैं।

यूनिवर्सल मेमोरी बनाने की दिशा में बढ़े कदम

वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की दुनिया में नई क्रांति की तैयारी कर ली है। **मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी (एमआइपीटी)** के वैज्ञानिकों ने **यूनिवर्सल मेमोरी** बनाने का तरीका खोजा है। **एटॉमिक लेयर डिपोजिशन (एएलडी) तकनीक** का इस्तेमाल करते हुए **टेंटेलम ऑक्साइड की मदद** से इस मेमोरी फिल्म को तैयार किया गया है।

क्या है

1. **यूनिवर्सल मेमोरी** की गति कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली अस्थायी **रैंडम एक्सेस मेमोरी (रैम)** जितनी ही तेज होगी और साथ ही इस पर जानकारियों को सुरक्षित रखना भी संभव होगा।
2. वर्तमान समय में कंप्यूटर या इस तरह के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में रैम के तौर पर अलग चिप का इस्तेमाल किया जाता है। उपकरण काम करते समय **इसी मेमोरी की मदद से प्रक्रियाओं को अंजाम देता है।**
3. तकनीकी रूप से देखा जाए तो कंप्यूटर पर किसी गणना को अंजाम देते हुए गिनती अस्थायी रूप से रैम पर आती है, वहीं गणना पूरी होती है और फिर नतीजा स्थायी मेमोरी पर सेव हो जाता है। उपकरण पर एक साथ कई प्रोग्राम चलाने के लिए ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है।
4. **स्थायी मेमोरी का प्रयोग गणना में या प्रोग्राम के चलने में इसलिए संभव नहीं होता,** क्योंकि उसकी गति रैम की तुलना में बहुत कम होती है। मेमोरी की गति प्रोसेसर के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम नहीं होती। यूनिवर्सल मेमोरी इस समस्या को दूर कर देगी। इसकी मदद से कंप्यूटर में रैम की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। स्थायी मेमोरी का इस्तेमाल ही रैम की तरह करना संभव होगा।
5. इससे कंप्यूटर की गति और क्षमता कई गुना तक बढ़ सकेगी। इस मेमोरी को रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी (रीरैम) कहा गया है। शोधकर्ता एंड्रे मार्कोव ने बताया कि टेंटेलम की मदद से रीरैम बनाने में कामयाबी मिली है। यह अभी प्रयोगशाला के स्तर पर है। बाहरी परिवेश में इसके सफल होने के बाद यूनिवर्सल मेमोरी का लक्ष्य दूर नहीं रह जाएगा।

200 से अधिक संभावित ग्रह खोजे गए

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा किया कि **केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप** ने हमारे सौर मंडल से बाहर मौजूद **219 नये ग्रह उम्मीदवारों** का पता लगाया है। शिन्हुआ के अनुसार, **केपलर मिशन ने 219** संभावित ग्रहों का एक सर्वे जारी किया है। ये सभी ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर हैं, जिनके बारे में **आकाशगंगा को स्कैन करने के लिए 2009 में शुरू की गई** अंतरिक्ष वेधशाला द्वारा पता लगाया गया था।

क्या है

1. **इनमें से 10 पृथ्वी के आकार के हैं,** ये दसों ग्रह अपने सूर्य के परिक्रमा उतनी ही दूरी से कर रहे हैं जितनी दूरी से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस कारण इन ग्रहों पर पानी और जीवन के अनुकूल अन्य स्थितियां हो सकती हैं।
2. **केपलर ने 4034 संभावित ग्रहों की खोज की है जिनमें से 2335 ग्रहों को एक्सोप्लेनेट बताया है।** इन 10 नए ग्रहों के सामने आने के बाद आकाशगंगा के आसपास रहने योग्य क्षेत्र (हैबिटेबल जोन) में मौजूद ग्रहों की संख्या 50 हो गई है।
3. केपलर टेलिस्कोप को ग्रहों की मौजूदगी का तब पता चला जब एक तारे की चमक में **मामूली बूंदे (मिनस्क्यूल ड्रॉप्स)** देखी गई। ये ड्रॉप्स तब आते हैं जब एक ग्रह तारे को पार करता है, इसे ट्रांजिट कहा जाता है।
4. नासा का कहना है कि ग्रहों की ये नई सूची संभावित ग्रहों का अभी तक किया गया सबसे ज्यादा पूर्ण और विस्तृत सर्वे है। टेलिस्कोप ने सिग्नस तारामंडल में 150000 तारों का अध्ययन किया है।
5. **वर्ष 2009 में केपलर स्पेसक्राफ्ट लांच किया गया था।** इसका मिशन हमारे गैलेक्सी के करीबी क्षेत्र में मौजूद एक्सोप्लेनेट का पता लगाना था।

अनोखा स्पेसक्राफ्ट विकसित

जाने-माने वैज्ञानिक **स्टीवन हॉकिंग एक ऐसा अंतरिक्षयान बना रहे हैं** जिसकी **गति प्रकाश की रफ्तार का पांचवां हिस्सा होगी।** यह स्पेसक्राफ्ट 25 साल के कम वक्त में ही अपने सबसे नजदीकी तारे पर पहुंचकर वहां की तस्वीरें धरती पर भेज सकेगा। हॉकिंग जिस स्पेसक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं, **उसका नाम 'स्टार चिप' है।** यह आकार में कुछ सेंटीमीटर का ही होगा और इसका वजन भी कुछ ग्राम ही होगा। **यह यान 10 करोड़ मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगा।** इस अंतरिक्षयान को धरती पर मौजूद एक सिस्टम से लेजर किरणों के द्वारा ऊर्जा दी जाएगी। इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में

बताते हुए हॉकिंग ने कहा, 'ऐसा सिस्टम एक घंटे से भी कम समय में मंगल ग्रह पर पहुंच सकता है। **प्लूटो पहुंचने में उसे केवल कुछ दिन लगेंगे।** 1977 में अंतरिक्ष में जो यान भेजा गया था, उसे यह स्पेसक्राफ्ट एक हफ्ते के अंदर ही पीछे छोड़ सकता है। यह स्पेसक्राफ्ट 20 साल में सौर मंडल के सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी पर पहुंच सकता है।'

क्या है

1. **इस यान का लक्ष्य इंसानों के रहने और जीने लायक एक दूसरा ग्रह खोजना होगा।** हॉकिंग ने बताया कि **अल्फा सेंटोरी पर पहुंचने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट उस स्टार सिस्टम में मौजूद ग्रहों की तस्वीरें ले सकता है।**
2. स्टार चिप वहां चुंबकीय क्षेत्रों व कार्बनिक अणुओं की भी जांच करेगा और फिर अपनी लेजर बीम तकनीक से उन आंकड़ों को धरती पर भेजेगा।
3. हॉकिंग ने यह भी बताया कि स्टार चिप शायद अल्फा सेंटुरी सिस्टम में मौजूद प्रॉक्सिमा बी नाम के उस ग्रह तक भी जाएगा, जो कि आकार में धरती के बराबर है और संभावित तौर पर जीवन के अनुकूल है।
4. हॉकिंग ने कुछ समय पहले कहा था कि आने वाले समय में धरती की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि यहां जी पाना इंसानों के लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार चिप अगर सौर मंडल के आसपास स्थित किसी जीवन के अनुकूल ग्रह की तस्वीरें भेजता है, तो यह इंसानों के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित होगा।
5. हॉकिंग ने कहा था कि अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उन्हें **धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर जाना होगा।** इंसानों के अस्तित्व को बचाने के लिए ही हॉकिंग इस बेहद खास स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं।

विविध

'ग्लोबल टेरर लिस्ट' में भारतीय

अमेरिका ने **कर्नाटक में जन्मे इस्लामिक स्टेट (आईएस) ऑपरेटर मोहम्मद शफी अरमर और दो अन्य को विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी (ग्लोबल टेररिस्ट) घोषित कर दिया है** और उनके खिलाफ **वित्तीय प्रतिबंध** भी लगा दिया है। अमेरिका ने आतंकी **अरमर, ओसामा अहमद अतार और मोहम्मद ईसा यूसुफ सकर अल बिनिलि** पर प्रतिबंध लगाया है। इन तीनों की आतंकी गतिविधियों से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था।

क्या है

1. **अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के साथ** मिलकर तीनों आईएस आतंकियों को ऑपरेटिव ऑफ फाइनेंस एसेट्स कंट्रोल की सूची में डाल दिया है। इसके तहत उनकी संपत्ति को ब्लॉक कर दिया गया और अमेरिकी नागरिकों को उनसे कोई संपर्क करने से मना कर दिया गया है।
2. स्टेट डिपार्टमेंट ने अरमर को भारत में आतंकियों की भर्ती करने वाले **विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) का लीडर बताया है।** इतना ही नहीं उसे आईएसआईएस ग्लोबल टेररिस्ट भी माना है।
3. स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अरमर भारत में कई दर्जन आईएसआईएस समर्थकों का समूह बनाया है जो पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे कि हमलों की साजिश रचने, हथियार खरीदने और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के लिए स्थानों की पहचान करता है।

मुंबई ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला

12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 16 जून को स्पेशल टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिसकी 19 जून को सुनवाई की जाएगी। इस मामले में **अबू सलेम समेत छह आरोपियों** को जस्टिस जी.एस. सानप की बेंच ने दोषी करार दिया है। टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को साजिश मामले में दोषी पाया और आरोपी अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया है। बता दें कि दाऊद के दुबई दफ्तर में कय्यूम मैनेजर **था। अबु सलेम, मुस्तफा, मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को 93 ब्लास्ट** का दोषी करार दिया गया है। **1993 में हुए इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे।**

क्या है

1. **मुकदमे का पहला पहला चरण 2007 में पूरा हुआ था।** इसमें कोर्ट ने 100 लोगों को दोषी ठहराया था और 23 लोगों को बरी कर दिया था।
2. सात आरोपियों **अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, करीमुल्ला खान, फीरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम का मुकदमा मुख्य मुकदमे से अलग कर दिया गया था।** क्योंकि इनकी गिरफ्तारी मुख्य मुकदमा पूरा होने के बाद हुई थी।
3. इस मामले में सलेम पर गुजरात से हथियार मुंबई ले जाने का आरोप है। मुस्तफा दोसा भारत में आरडीएक्स समेत विस्फोटकों को लाने का आरोपी है। **सलेम ने एके-56 राइफलें, 250 बुलेट** और कुछ हैंड ग्रेनेड अभिनेता संजय दत्त को उनके आवास पर 16 जनवरी 1993 को सौंपे थे। दो दिन बाद सलेम और दो अन्य लोग दत्त के घर से दो राइफल और कुछ गोलियां ले गए थे।

क्या था मामला

1. **12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे।** बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
2. बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।
3. **साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई.** इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी। ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।

भारतीय न्यूक्लियर फ्यूझन के पिता का निधन

भारतीय न्यूक्लियर फ्यूझन रिऐक्टर रिसर्च प्रोग्राम के पिता कहे जाने वाले **प्रोफेसर पी कृष्ण काव** का निधन हो गया। **काव इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाजमा रिसर्च (IPR) गांधीनगर के फाउंडर डायरेक्टर भी थे।** यह संस्थान दुनिया के सबसे बड़े फ्यूझन एक्स्पेरिमेंट का हिस्सा है।

क्या है

1. **काव इंटरनैशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्स्पेरिमेंटल रिऐक्टर (ITER) के काउंसिल साइंस ऐंड टेक्नॉलजी अडवाइजरी कमिटी के 2007-09 तक चेयरमैन भी रह चुके थे।**
2. कश्मीर में जन्मे काव का जन्म कश्मीर में हुआ था। वह शुरू से ही पढ़ने में मेधावी थे।
3. काव ने महज 16 साल की उम्र में ही गाजियाबाद के MMH कॉलेज से MSc पास कर लिया था।
4. उन्होंने आईआईटी दिल्ली से महज 18 साल की उम्र में ही पीएचडी की उपाधि हासिल कर ली थी।

एडुअर्ड फिलिप फिर बने फ्रांस के प्रधानमंत्री

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दूसरे चरण के संसदीय चुनाव के बाद एडुअर्ड फिलिप को फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मैक्रों के कार्यालय सूत्रों ने बताया कि फिलिप को नई सरकार का गठन करने को कहा गया है।

क्या है

1. फिलिप नई सरकार का गठन करेंगे। दूसरे चरण के मतदान में मैक्रों की पार्टी को नेशनल असेंबली में भारी बहुमत मिली है।
2. इस जीत से उनके **यूरोपीय संघ (ईयू) समर्थक** और कारोबार अनुकूल एजेंडे को जारी रखने का जनादेश मिला है।
3. उनकी पार्टी आरईएम और सहयोगियों ने नेशनल असेंबली की 577 सीटों में से 350 सीटों पर जीत दर्ज की। मैक्रों मई में फ्रांस के राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार संसदीय चुनाव हुए हैं।

जीएसटी के ब्रांड एंबेसडर

बॉलीवुड के महानायक **अमिताभ बच्चन माल एवं सेवाकर (GST) का प्रचार करते नजर आएंगे।** उल्लेखनीय है कि देश में जीएसटी की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई से लागू होनी है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क विभाग बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एंबेसडर बनाएगा। उनके साथ 40 सेकेंड की एक विज्ञापन फिल्म पहले ही शूट कर ली गई है। इससे पहले **बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू जीएसटी की ब्रांड एंबेसडर थीं।**

ग्रामीण विकास में प्रभावी पहल के लिए पुरस्कार

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19 जून, 2017 को एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियां दर्शाई गईं। इस समारोह में विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रशंसनीय कार्य करने वाले राज्यों, संस्थानों तथा सरकारी पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। **जियो-मनरेगा के तहत जल संरक्षण पर लघु फिल्म, मध्य प्रदेश की सौ वर्षीय जनजातीय महिला, जदिया बाई के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण तथा पीएमजीएसवाई पर शान द्वारा गाए गए एक दृश्य श्रव्य गीत का भी प्रदर्शन किया गया।** ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा पर एक नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप की भी शुरूआत की जिसमें मनरेगा के विभिन्न पहलुओं पर सूचना प्रदान की जा सकती है। ग्रामीण विकास विभाग अपने कार्यक्रम प्रबंधन में सूचना और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग करता है और **'जन-मनरेगा' ऐप 'मेरी सड़क' और 'आवास'** मोबाइल ऐप विभाग की तीसरी ऐसी नागरिक केंद्रित पहल है।

क्या है

1. **विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 144 पुरस्कार दिए गए। सतत आजीविका, पारदर्शिता और जवाबदेही, आधार सीडिंग, रूपांतरण और जियो-मनरेगा** पर पुरस्कार मनरेगा के तहत दिए गए थे।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंर्तगत सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण वाले (बिहार) तथा गैर-परम्परागत निर्माण सामग्री का उपयोग करने वाले (मध्य प्रदेश) राज्यों को पुरस्कार दिए गए।
3. **हरियाणा, गुजरात तथा कर्नाटक** ने पीएमजीएसवाई (चरण 1 और 2) में लक्ष्य का 95 प्रतिशत से अधिक काम पूरा करने पर विशेष पुरस्कार प्राप्त किए। ऐसे राज्यों को जिन्होंने विभिन्न मापदंड़ों से अच्छा काम किया था उन्हें पीएमएवाई-जी के अंर्तगत पुरस्कृत किया गया, केंद्रीय भवन अनुसंधान, रुड़की जिसने भवन टाइपोलाजी का तकनीकी परीक्षण उपलब्ध करवाया, ग्रामीण विकास की एनआईसी विभागीय टीम द्वारा तकनीकी सहायता दिए जाने तथा नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यूएनडीपी के सलाहकार, वरिष्ठ नागरिक डॉ. प्रबीर कुमार दास को भी पुरस्कार दिए गए।
4. नौ जिलों के कलैक्टरों को भी अधिकतम संख्या में पीएमएवाई-जी मकान पूरे करने के लिए पुरस्कृत किया गया, महत्वपूर्ण बात यह रही कि नौ जिला कलैक्टरों में से पांच उड़ीसा से थे।
5. राष्ट्रीय संसाधन संगठन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवसीज बैंक, यूको बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा आईसीआईसीआई बैंक को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। जिन राज्यों को विभिन्न श्रेणियों के अंर्तगत पुरस्कार मिले उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल शामिल थे। कौशल विकास श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ निष्पादन राज्य, सर्वश्रेष्ठ चेम्पियन नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण भागीदारों को पुरस्कृत किया गया।
6. **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद द्वारा किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति भी थी। मूल्यांकन रिपोर्ट ने कार्यक्रम की मुख्य प्रबलता को उजागर किया और पूरे देश में इस कार्यक्रम को सुदृढ़ और विस्तृत करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में दूसरे नंबर पर है भारत

भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं। दुनिया में जितने लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है **उनमें चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर है।** भारत में वायु प्रदूषण चीन से भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण के **प्रमुख प्रदूषक तत्व पार्टिकुलेटेड मैटर (पीएम) 2.5 के कारण दुनिया भर में 42 लाख**

लोग समय से पहले मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। इनमें से 10 लाख से ज्यादा मौतें अकेले भारत में हो रही हैं। चीन के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है, जहां वायु प्रदूषण से इतनी मौतें हो रही हैं। इसका मुख्य कारण भारत में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।

क्या है

1. **प्रदूषण से भारत में 33 फीसद मौतें बढ़ी हैं। 1990 के बाद भारत में जहां ओजोन गैस से सालाना औसतन 20 फीसद मौतें बढ़ रही हैं।**
2. वहीं चीन में यह दर मात्र 0.50 फीसद है। भारत में ओजोन से होने वाली असामयिक मौतें भी बांग्लादेश से 13 गुना और पाकिस्तान से 21 गुना ज्यादा है।
3. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2015 में पीएम 2.5 से दुनिया भर में हुई मौतों में 52 फीसद मौतें भारत और चीन में हुईं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017 शीर्षक वाले जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद चीन में जहां इन मौतों की संख्या 17.22 फीसद बढ़ी है वहीं भारत में यह इजाफा 48 फीसद तक दर्ज किया गया है।
4. इस रिपोर्ट के मुताबिक **2015 में चीन में प्रदूषण से 11.08 लाख, भारत में 10.90 लाख, यूरोप में 2.57,** रूस में 1.37 लाख, पाकिस्तान में 1.35 और अमेरिका में 88 हजार जानें गई हैं।
5. यह पड़ोसी देश बांग्लादेश से नौ गुना जबकि पाकिस्तान से आठ गुना ज्यादा है। पीएम 2.5 कण प्रदूषण से बीमारियों की सबसे बड़ी वजह हैं। इसका एक कारण यह भी है कि विश्व की करीब 92 फीसद आबादी जहां रहती है वहां स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं है। वहीं चिकित्सा क्षेत्र की पत्रिका द लांसेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में हर मिनट दो लोगों की मौत होती है।
6. **विश्व के कई सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में हैं।** दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है जबकि विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण घरेलू बाजार को श्रम में कमी के कारण आय में 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है।
7. **पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही छोटा कण होता है जिसमें कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाईऑक्साइड इत्यादि तत्व होते हैं** जिसके कारण यह हवा को प्रदूषित करते हैं।

आतंकी फंडिंग पर बेनकाब हो गया पाक

आतंकी फंडिंग के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए बने अंतरराष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की रिपोर्ट में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों व व्यक्तियों के वित्तीय लेन-देन पर रोक नहीं लगाने का दोषी पाया गया है। भारत ने एफएटीएफ में पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रही फंडिंग का मुद्दा उठाया था।

क्या है

1. **स्पेन में 18 से 23 जून तक हुई एफएटीएफ की प्लेनरी बैठक** में पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को मिल रही फंडिंग पर रिपोर्ट पेश की गई। इसमें कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रतिबंधित आतंकी संगठन पाकिस्तान में खुलेआम सक्रिय हैं और आर्थिक लेन-देन कर रहे हैं।
2. पाकिस्तान इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। सभी सदस्य देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मामला इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप (आइसीआरजी) को सौंप दिया। बाद में आइसीआरजी ने एशिया पैसिफिक ग्रुप (एजीपी) को एक महीने के भीतर पाकिस्तान द्वारा आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देने को कहा है। ताकि जुलाई में होने जा रही एजीपी की वार्षिक बैठक में इस पर चर्चा की जा सके।
3. **भारत ने पिछले साल अक्टूबर में भी पेरिस में हुई एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को हो रही भारी फंडिंग का मुद्दा उठाया था।**

4. भारत का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों की सूची में डाले गए लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और आतंकी हमलों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए भारत ने कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे।
5. भारत के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए **एफएटीएफ ने इसकी जांच का फैसला किया** और एशिया पैसिफिक ग्रुप को इस पर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। लेकिन एशिया पैसिफिक ग्रुप के सदस्यों को पाकिस्तान प्रभावित करने में सफल रहा और रिपोर्ट तैयार नहीं होने दी।
6. इसके बाद भारत ने फरवरी में एफएटीएफ की बैठक में फिर यह मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान की ओर से इसका तीखा विरोध हुआ। पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस मुद्दे को तकनीकी पहलुओं में उलझा दिया जाए। लेकिन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के भारत के प्रस्ताव पर मिले समर्थन से पाकिस्तान की मंशा सफल नहीं हो सकी। एफएटीएफ बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्पेन के वेगा सेरानो ने पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग पूरी तरह रोकने के लिए तीन महीने का नोटिस थमा दिया।

पाकिस्तान के अलावा इन देशों को मिला ऐसा दर्जा

ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, जॉर्डन, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, बहरीन, फिलीपींस, थाईलैंड, कुवैत, मोरक्को, अफगानिस्तान, ट्यूनीशिया

पेड न्यूज के मामले में EC की बड़ी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक **नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले** में यह फैसला सुनाया गया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी दोनों चली जाएगी। अब **वे तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।** उधर मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यह वर्तमान का चुनाव नहीं है, यह 2008 का चुनाव है। इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना। फैसला लेने से पहले मेरे पक्ष को नहीं देखा गया।

क्या है

1. दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष **2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत** चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।
2. चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर **नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया था।**
3. चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया।

अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल के तीसरे यात्री

अमरीका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल के **39 वर्षीय राजा चारी** को अंतरिक्ष यात्री को उड़ान भरने के लिए चुना है। भारतीय मूल के **कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स** के बाद **राजा चारी तीसरे ऐसे भारतीय मूल के अन्तरिक्ष यात्री होंगे,** जो नासा के अन्तरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। राजा चारी का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें चुना गया है। यह सब सपने जैसा लग रहा है। उन्होंने बताया कि भारत से उनके परिवार वाले बधाई के संदेश भेज रहे हैं। **उनके पिता का निधन 2009 में हो गया था।** उनके परिवार के बहुत से लोग अब भी भारत में रहते हैं।

क्या है

1. **चारी विस्कॉसिन के मिलवौकी शहर में जन्मे** और उन्होंने आयोवा के सीडर फाल्स शहर में स्कूली पढ़ाई की।
2. अब वह **वाटरलू शहर में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं।** चारी ने 1999 में अमरीकी वायु सेना अकादमी से एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में एमआईटी से एस्ट्रोनॉटिक्स और एयरोनॉटिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की।

3. **राजा चारी अमरीकी वायु सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं।** अमरीकी वायु सेना के लिए राजा चारी ने इराक युद्ध के दौरान एफ-15ई लड़ाकू विमान की उड़ानें भी भरी थीं।
4. **2013 में पहली बार चारी ने नासा के लिए कोशिश की थी लेकिन उस बार नहीं चुने गए थे।**

कनाडा सुप्रीम कोर्ट की पहली सिख महिला जज

भारतीय मूल की पलबिंदर कौर शेरगिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ **ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा की पहली अमृतधारी(पगड़ीधारी) सिख महिला जज बनी हैं।** शेरगिल ने जस्टिस अरनॉल्ड बेली का स्थान लिया है जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

क्या है

1. **कनाडा में पलबिंदर कौर की पहचान मानवाधिकार के बड़े वकील के रूप में रही है।** कनाडा के विधि मंत्री व अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन ने शेरगिल की नियुक्ति की घोषणा की।
2. **वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मुखबिर सिंह** ने कहा कि यह कनाडा में रह रहे सिख समुदाय के लोगों के लिए एक और मील का पत्थर है। वह कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय के कई मामलों की अदालत में पैरवी कर चुकी हैं।

सुपरकंप्यूटर से आठ गुना तेज सुपरकंप्यूटर बना रहा चीन

चीन के इंजीनियर इन दिनों एक ऐसा सुपरकंप्यूटर बना रहे हैं, जो **मौजूदा वक्त के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर से भी आठ गुना तेज होगा।** फिलहाल **इसका तीसरा प्रोटोटाइप विकसित किया जा रहा है।** इंजीनियरों की योजना इस प्रोटोटाइप को अगले साल जून तक लॉन्च करने की है। प्रोटोटाइप को पूर्वी चीन में शैनडोंग प्रांत के जिनान में स्थित **नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एनआरसीपीसी)** और नेशनल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर बना रहे हैं। **सनवे नाम से बनने वाला यह सुपरकंप्यूटर 'एक्सास्केल कंप्यूटर' होगा।** इससे चीन को अंतरिक्ष, चिकित्सा, समुद्र और मौसम सहित कई क्षेत्रों से संबंधित शोध कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इंजीनियरों को उम्मीद है कि **प्रोटोटाइप बन जाने के बाद वह सुपरकंप्यूटर को 2020 तक बाजार में लाने की स्थिति में होंगे।**

क्या है 'एक्सास्केल कंप्यूटर'

1. **यह कंप्यूटर एक सेकेंड में एक क्विंटिलियन (1 के पीछे 18 शून्य) गणनाएं करने में सक्षम होगा।**
2. फिलहाल दुनिया में जो सबसे तेज सुपरकंप्यूटर मौजूद है, वह **प्रति सेकेंड 93 क्वाड्रिलियन (1 के पीछे 15 शून्य) गणनाएं करने में सक्षम है।**

दुनिया के शीर्ष सुपरकंप्यूटर

नाम	स्थान	गति (पेटाफ्लॉप्स में)	देश
सनवे ताइहूलाइट	1	93	चीन
तियानहे-2	2	33.9	चीन
पिज डाएंट	3	19.6	स्विट्जरलैंड
टाइटन	4	17.6	अमेरिका
सिक्योइया	5	17.2	अमेरिका
सहस्र टी	133	0.90	भारत

हर साल एक अरब पौधे लगाने वाले ड्रोन हुए तैयार

वैज्ञानिकों ने ऐसे ड्रोन विकसित किए हैं जो **हर साल एक अरब पौधे लगा सकेंगे।** साथ ही पौधरोपण के अनुकूल जगहों की पहचान करेंगे। **यह घट रहे वनक्षेत्र की कमी को पूरा करने में काफी हद तक सहायक होगा।** ड्रोन सिस्टम को **ब्रिटिश कंपनी बायोकार्बन इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है।** यह प्रणाली जमीन की बारीकी से पड़ताल कर पौधों को लगाने के लिए अनुकूल स्थलों की पहचान करेगी। इसके बाद ड्रोन के जरिये मिट्टी में अंकुरित बीजों की बुआई होगी।

क्या है

1. शोधकर्ताओं के अनुसार, **नए ड्रोन के जरिये उन खड़ी ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भी पौधरोपण किया जा सकेगा** जहां पहुंचना लगभग असंभव होता है।
2. पौधे लगाने के लिए संभावित जगहों की पहचान को ड्रोन के उपयोग से इलाके का मानचित्र तैयार किया जाता है।
3. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, **वनों की कटाई के चलते दुनिया में 17 फीसद कार्बन का उत्सर्जन होता है।** यह आंकड़ा परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन से भी कहीं ज्यादा है।
4. शोधकर्ताओं के अनुसार, **धरती से हर साल 15 अरब पेड़ कम हो जाते हैं।** ज्यादातर पेड़ों की कटाई दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए अन्न पैदा करने को खेत लायक जमीन बनाने को की जाती है।
5. वनों की तेज होती कटाई से जलवायु परिवर्तन की स्थिति और खराब हो सकती है।

ग्रैंडस्लैम में एंट्री मारते ही मिली पहली जीत

भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी जीवन **नेदुनचेझियान ने विंबलडन में कमाल कर दिखाया। पहली बार ग्रैंडस्लैम खेल रहे पुरुष युगल मुकाबले में** जीवन और ऑस्ट्रेलिया के मैट रीड ने न्यूजीलैंड के माइकल वीनस और अमेरिका के रेयॉन हैरिसन को 6-3, 3-6, 10-7 से हराया। **जीवन नेदुनचेझियान को पिछले 24 घंटे के दौरान मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा** और विंबलडन में खेलने के लिए हां के इंतजार में वह काफी तनाव से गुजरे और अंततः इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेलने का उनका सपना साकार हो गया।

क्या है

1. **अपने करियर में पहली बार जीवन को ग्रैंडस्लैम में पदार्पण का मौका मिला** लेकिन उनके जोड़ीदार हियोन चुंग के टखने की चोट ने उनके सपने को लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन तभी **अमेरिका के जेयर्ड डोनाल्डसन उनके लिए फरिश्ते के रूप में सामने आए** और भारत के इस खिलाड़ी के साथ खेलने को राजी हो गए।
2. इन दोनों की संयुक्त रैंकिंग 160 (जीवन की 95 और जेयर्ड की 65) है जो पुरुष युगल ड्रा में सीधे प्रवेश के लिए कट आफ रैंकिंग है।

आधार नहीं होने पर सरकारी लाभ से नहीं किया जाएगा वंचितः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास **आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं हैं।** कोर्ट ने कहा कि **ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।** उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ लॉयर श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं से बहस के दौरान कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में किसी को भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक **संवैधानिक पीठ इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं करती है** तब तक आधार योजना को आवश्यक नहीं किया जा सकता है।

क्या है

1. शुरुआत में **उच्चतम न्यायालय ने आईटीआर फाइल करने के लिए आधार कार्ड के पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट ने स्थिर रखा था।** जिसके बाद आयकर विभाग ने इस मामलें में लोगों को अपना **आधार पैन से लिंक करने के लिए उत्साहित किया था।**
2. **आयकर अधिनियम की धारा 139एए** के लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)** ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आधार प्राप्त करने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने आधार का नाम या उनके आधार नामांकन आईडी की संख्या साथ ही उनके स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन भी देना पड़ेगा।
3. एक ऐतिहासिक फैसले में, **सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 139एए को संवैधानिक रूप से मान्य कर दिया,** जिसके लिए आधार संख्या में पैन के लिए आवेदन करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता थी।

4. सरकार की ओर से लिए गए ताजा निर्णय के मुताबिक अब **आधार नंबर नया बैंक खाता खुलवाने के लिए भी जरूरी कर दिया गया है।** साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए भी अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
5. गौरतलब है कि सरकार ने इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। वहीं पुराने बैंक खाताधारकों को भी अपना आधार 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर खाते वैध नहीं रहेंगे। ऐसे में सभी नए पुराने खाताधारकों के लिए बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है।

राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2015 प्रदान किये

राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार समारोह 2015 आयोजित किया गया। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्री **श्री कलराज मिश्र ने एमएसएमई पुरस्कार 2015 प्रदान किये।** संयुक्त राष्ट्र ने जब से **27 जून को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस घोषित किया है,** तब से लेकर अब तक **सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय** इस दिन का चयन एमएसएमई को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए करता आया है। एमएसएमई को ये पुरस्कार उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिये जाते हैं। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन एमएसएमई क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले उन उद्यमों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

क्या है

1. इस अवसर पर केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्र ने **'डिजिटल एमएसएमई योजना'** का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने **एसएपी इंडिया, इंटेल और एचएमटी को तीन सहमति पत्र (एमओयू) सौंपे।**
2. इन कदमों से **डिजिटल इंडिया मिशन** को सफल बनाने की दिशा में मंत्रालय द्वारा किये जा रहे प्रयासों को नई गति मिलेगी। **डिजिटल एमएसएमई योजना क्लाउड कम्प्यूटिंग पर केन्द्रित है,** जो एमएसएमई द्वारा अपने यहां स्थापित किये गये आईटी बुनियादी ढांचे की तुलना में एक किफायती एवं लाभप्रद विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है।
3. **क्लाउड कम्प्यूटिंग के तहत एमएसएमई अपनी कारोबारी प्रक्रियाओं के समुचित प्रबंधन के लिए साझा एवं खुद के लिए स्थापित किये गये** सॉफ्टवेयर सहित आईटी बुनियादी ढांचे तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु इंटनेट का इस्तेमाल करते हैं।
4. क्लाउड कम्प्यूटिंग के तहत हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं पर कुछ भी निवेश नहीं करना पड़ता है। अत: **'कैपेक्स' ऐसी स्थिति में 'ओपेक्स' में परिवर्तित हो जाता है।** इस योजना से एमएसएमई अपने यहां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को उपयोग में लाने के लिए इस नई अवधारणा अर्थात क्लाउड कम्प्यूटिंग को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
5. केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्र ने इस अवसर पर यह जानकारी दी कि **वर्ष 2015 में विभिन्न श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या 56 है,** जिनमें एमएसएमई के लिए 50 और बैंकों के लिए 6 पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एमएसएमई मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' विजन के अनुरूप अथक प्रयास कर रहा है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र के अन्य उद्यम भी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा स्थापित किये गये उदाहरणों का अनुकरण करेंगे।

साइबर अटैक की चपेट में विश्व की कई कंपनियां

27 जून **को रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी, यूक्रेन के बैंक व मल्टीनेशनल कंपनियां साइबर अटैक की चपेट में आ गयी।** यह हमला उसी तरह के वायरस के कारण हुआ है जिसने पिछले माह 300,000 से अधिक कंप्यूटरों को अपने चपेट में ले लिया था। **यूक्रेन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।** बताया जा रहा है कि यहां सबकुछ ठप्प हो गया है। रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के सिस्टम भी हैक कर लिए गए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने देश के पॉवर ग्रिड और साथ ही बैंकों, सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटरों में गंभीर घुसपैठ की जानकारी दी है।

क्या है

1. इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हमला यूरोप से बाहर तक फैल चुका है। अमेरिकी दवा कंपनी मर्क ने कहा कि उसके कंप्यूटर सिस्टम भी हमले का शिकार हुए हैं।
2. **रैनसमवेयर के हमलों से सचेत** और इस पैनी नजर रखने वाले साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों की मानें, तो मई के महीने में ही दुनिया के 150 देशों में कंप्यूटरों पर वार करने वाले **रैनसमवेयर वानाक्राई** के चलते भारत में करीब 40,000 से अधिक कंप्यूटर साइबर हमलों की चपेट में आए थे। इस हमले के साथ रैनसमवेयर के हमलों के शिकार देशों में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश रहा है।
3. यह संभावना जतायी जा रही है कि यह हमला यूक्रेन से किया गया है। इसमें **'Eternal Blue' नामक कोड है** जिसके बारे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी (NSA) से चोरी हुई और पिछले माह रैनसमवेयर अटैक 'वानाक्राई' में भी इसका उपयोग किया गया।

मानव तस्करी के मामले में चीन सबसे खराब देश

चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच वो **मानव तस्करी जैसे अपराधों पर गंभीर नजर नहीं आ रहा है।** 27 जून को **अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट** ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें **चीन को मानव तस्करी के मामले में सबसे खराब देशों की सूची में शामिल किया गया है।** चीन के अलावा इस सूची में **वेनेजुएला, बेलीज, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया** जैसे देश भी शामिल हैं।अमेरिका का मानना है कि चीन मानव तस्करी को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करता नहीं दिख रहा है। चीन में मानव तस्करी करने वाले बहुत कम लोगों तक ही कानून की हाथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में मानव तस्करों के हौसले बुलंद नजर आते हैं।

क्या है

1. मानव तस्करी मौजूदा समय का सबसे दुखद मुद्दों में से एक है। यह परिवारों को तोड़ता है, वैश्विक बाजारों को विकृत करता है, कानून के शासन को नजरअंदाज करता है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
2. यह रिपोर्ट बताती है कि चीन मानव तस्करी से निपटने के लिए गंभीर कदम नहीं उठा रहा है। इसलिए ये अपराध बढ़ता चला जा रहा है। चीन के कुछ क्षेत्रों की स्थिति तो बेहद खराब है।
3. अमेरिका का आरोप है कि **चीन के शिनजियांग प्रांत के वीगर मुसलमानों से जबरदस्ती काम कराया जाता है।** यहां लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। हालांकि स्थानीय सरकार ने एक नोटिस जारी करके यह दावा किया है कि इसे पूरी तरह से बंद किया जा चुका है।
4. रिपोर्ट की प्रस्तुति के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी मौजूद थी। इवांका राष्ट्रपति के सलाहकार सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में से एक मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई भी है, जो **दुनिया भर में करीब 20 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है।**

11वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया

भारत सरकार ने वर्ष **2007 में दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सांख्यिकी, सांख्यिकी प्रणाली और आर्थिक नियोजन के क्षेत्रों में** उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए प्रोफेसर महालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर मनाये जाने वाले विशेष दिवसों के वर्ग में **'सांख्यिकी दिवस'** के रूप में निर्दिष्ट किया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य **सामाजिक-आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी के महत्व की जन जागरूकता पैदा करना** और प्रोफेसर महालनोबिस के योगदान को स्वीकार करते हुए उनको श्रद्धांजलि देना है। प्रत्येक वर्ष गंभीर चर्चा हेतु **राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक थीम का चयन किया जाता है** और वर्षभर उस चयनित क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

क्या है

1. **सांख्यिकी दिवस की इस वर्ष की थीम 'प्रशासनिक सांख्यिकी' है।** प्रशासनिक सांख्यिकी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह लागत और समय कुशल है, सैंपल सर्वेक्षण और जनगणना पर निर्भरता को कम करती है।

2. **प्रोफेसर महालनोबिस ने वर्ष 1931 में कोलकता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी।** संसद ने वर्ष 1959 में एक अधिनियम पारित करके इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करके **कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय का एक स्वायत संस्थान बना दिया गया।**
3. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान 29 जून को 'कर्मिक दिवस' मनाता है।** इस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने मिलकर 29 जून को कोलकता में प्रोफेसर महालनोबिस का जन्मोत्सव मनाया।
4. **29 जून, 2017 को प्रो. पीसी महालनोबिस के 125वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम किया गया।** 11वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कोलकाता स्थित महालनोबिस भवन, बारानगर में प्रो. पीसी महालनोबिस पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

भारत के नए अटर्नी जनरल

सीनियर ऐडवोकेट **के.के. वेणुगोपाल को भारत के नए अटर्नी जनरल होंगे।** अटर्नी जनरल के तौर पर नियुक्ति के लिए वेणुगोपाल का नाम तय कर दिया गया है। इससे पहले **अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी** ने अपने कार्यकाल को आगे न बढ़ाने की गुजारिश की थी। 86 साल के वेणुगोपाल की नियुक्ति के प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट से पहले विचार किया गया था।

क्या है

1. **वेणुगोपाल जानेमाने संवैधानिक विशेषज्ञ हैं** और उन्हें **पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।**
2. मोरारजी देसाई सरकार के वक्त वेणुगोपाल अडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं।
3. हाल में 2 जी मामले में वह सीबीआई और ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं।
4. वेणुगोपाल जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए एनजेएसी के पक्ष में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने केंद्र सरकार के कानून का पक्ष लिया था।
5. अयोध्या विवाद मामले में कल्याण सिंह सरकार के लिए वह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे।

ब्रिटिश महारानी ने किया अंकित कवात्रा को सम्मानित

भूख की समस्या पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अंकित कवात्रा को ब्रिटिश महारानी के **यंग लीडर्स अवार्ड** से सम्मानित किया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें **बकिंघम पैलेस** में यह सम्मान दिया।

क्या है

1. 25 वर्षीय अंकित भारत में भूख और कुपोषण की समस्या के हल की दिशा में काम करते रहे हैं। वह **'फीडिंग इंडिया' संगठन के संस्थापक हैं।**
2. उन्होंने इसकी शुरुआत 2014 में भूख और भोजन की बर्बादी के मसलों का हल निकालने के लिए की थी। तब उनके साथ महज पांच लोग जुड़े थे।
3. **अब भारत के 43 शहरों में उनके संगठन से करीब साढ़े चार हजार स्वयंसेवक जुड़े हैं।** वे शादी समारोह और पार्टियों से बचने वाले भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद करते हैं।
4. अंकित ने कहा, श्बकिंघम पैलेस में महारानी के हाथों सम्मानित होना गर्व की बात है। यह उसी तरह का सम्मान है जिसे मैं सपने भी नहीं सोच सकता था।
5. संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल अंकित समेत 17 लोगों को यंग लीडर्स के तौर पर चुना था। इन्हें सतत विकास लक्ष्यों में मदद के लिए चयनित किया गया था।

50 फीसद मौतों का कारण पता नहीं

मेडिकल साइंस ने खूब तरक्की कर ली है। आज के दौर में बड़ी-बड़ी बीमारियों का न सिर्फ शुरुआती चरण में ही पता लगा लिया जाता है, बल्कि काफी हद तक इलाज भी संभव है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जिनका इलाज आज भी संभव नहीं है। इसके बावजूद **दुनियाभर में हर साल होने वाली करोड़ों मौतों में से 50 फीसद से ज्यादा मौतों के**

कारणों का पता ही नहीं चल पाता। यह दावा **विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)** ने एक ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट में किया है। संगठन के अनुसार इस कारण लोगों के **बेहतर स्वास्थ्य के लिए नीति निर्माण** और उसके क्रियांवयन में समस्या आती है। रिपोर्ट में एचआइवी व नवजातों की मौत के आंकड़े भी हैं।

एसडीजी पर केंद्रित है रिपोर्ट

1. **ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर केंद्रित है।** 2030 तक जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए इन लक्ष्यों को 2015 में तय किया गया था।

मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट

1. मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। **2015 में विश्व में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार पर 19 थी।**
2. पांच साल से कम बच्चों की मौतों का आंकड़ा प्रति एक हजार पर 43 था। 2015 में प्रति एक लाख पर मातृ मृत्यु दर 216 थी।
3. इस आंकड़े को 2030 तक 70 पर लाने का लक्ष्य है। अब भी करीब 830 महिलाओं की मौत रोजाना शिशु को जन्म देने संबंधी कारणों से होती है।

क्यों जरूरी है मौतों के कारणों का पता चलना

1. किसी भी देश की **स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन** करने के लिए मौत का कारण पता करना बेहद जरूरी है।
2. यह वह तरीका है, जिसके जरिए भविष्य की योजनाएं बनायी जा सकती हैं। इसके जरिए ही आने वाले खतरे को पहले से ही भांपा जा सकता है। इस बारे में असिस्टेंट डायरेक्टर-जनरल ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड इनोवेशन, डब्ल्यूएचओ मैरी पॉल केनी कहती हैं, 'नागरिकों की मौत और बीमारी का क्या कारण है, अगर देश इससे अनजान रहेंगे तो उनकी बेहतरी के लिए क्या करना है, यह जानना भी कठिन होगा। डब्ल्यूएचओ इस दिशा में देशों के साथ काम कर रहा है।'

एचआइवी संक्रमण घटा

1. **साल 2015 में एचआइवी संक्रमण के 21 लाख नए मामले सामने आए।** यह 2000 की तुलना में करीब 35 फीसद कम हैं। 2000 में करीब 32 लाख नए मामले सामने आए थे।
2. मौत के कारणों का पता लगाने और उसे दर्ज करने के मामले में **चीन, तुर्की और ईरान** ने सर्वाधिक प्रगति की है।
3. वहां 90 फीसद मौतों के कारणों का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है। 1999 में यह आंकड़ा महज पांच फीसद था।

भारत की स्थिति

1. दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत काफी पिछड़ा हुआ है। **विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य साख्यिकी रिपोर्ट 2017** के अनुसार भारत में प्रत्येक 10 मौतों में से सिर्फ एक का ही पंजीकरण होता है।
2. यह तो बात पंजीकरण की है, जबकि मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम का आंकड़ा तो और भी कम है।

ब्रिटेन की अगली PM थेरेसा मे

ब्रिटेन में हुए प्रधानमंत्री चुनाव के लगभग तीन हफ्ते बाद **थेरेसा मे को अंतत: ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुन लिया गया है।** अपने भाषण के दौरान उन्होंने आम मतों से ये जीत हासिल की। गर्भपात नियमों पर अपने एजेंडे को लेकर उन्होंने पूर्व सरकार के समक्ष चुनौती पेश की थी। अपने एजेंडे में थेरेसा ने घोषणा की थी कि वे **उत्तरी आयरिश महिलाओं के लिए गर्भपात निधि बनाएंगी।**

क्या है

1. **322 सांसदों ने मे के एजेंडे के पक्ष में मतदान किया,** जबकि 309 ने उनके विपक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिने समर्थन जीतने में नाकाम रहे।
2. टोरी नेताओं के लिए एक और प्रोत्साहन की बात तब हो गई जब दर्जनों सांसदों ने जेरेमी कोर्बिन्स के ब्रेक्सिट रुख के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बाजार में ब्रिटेन को बनाए रखने के लिए प्रस्ताव का समर्थन किया।
3. ब्रिटेन में क्वीन के भाषण के आधार पर मिले मतों को सरकार के रूप में विश्वासमत माना जाता है। 8 जून को सामान्य चुनाव में हार होने के बावजूद, पार्टी ने कहा कि उन्हें सरकार में आने का पूरा भरोसा था।